



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) का वर्ष 2023-2024  
की अनुदानों की पूरक मांगें तथा वर्ष 2024-2025 का अंतरिम बजट

**निर्मला सीतारामन**

वित्त मंत्री

का

भाषण

**Supplementary Demands for Grants 2023-2024 and Interim Budget 2024-2025 of the  
Union Territory of Jammu & Kashmir  
(With Legislature)**

**SPEECH  
OF  
NIRMALA SITHARAMAN  
MINISTER OF FINANCE**

**फरवरी / February 5, 2024**



जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित) का वर्ष 2023-24 की अनुदान की पूरक मांगें तथा वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

का भाषण

अध्यक्ष महोदय,

1. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अगस्त 2019 के परिवर्तनकारी सुधारों के बाद से सामाजिक-आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार त्वरित और समावेशी विकास के मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए प्रतिबद्ध है और यह नागरिकों को अपना भविष्य सँवारने और नई आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनाती है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार के दीर्घकालिक विजन में सुशासन और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने, सतत कृषि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
2. वर्ष 2019 में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा शासन संरचना को विकेंद्रीकृत बनाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, दक्षता में सुधार और सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता, राजस्व सृजन बढ़ाने, व्यर्थ व्यय को कम करने और अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ाने के लिए नए उपाय संभव हुए हैं।
3. सरकार ने आर्थिक और सामाजिक विकास पहलों को कार्यान्वित करने के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून और व्यवस्था को सही ढंग से बनाये रखा हुआ है। सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी और निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रभावी उपायों और प्रयासों के कारण, जम्मू और कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है।
4. **शासन का विकेंद्रीकरण**
  - क. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवाज को मजबूत करने और शासन के विकेंद्रीकरण के लिए, संविधान में 73<sup>वाँ</sup> संशोधन किया गया और वर्ष 2020 में जम्मू और कश्मीर पंचायती राज

अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया। तीन महत्वपूर्ण 'एफ' - निधि, कार्य और पदाधिकारी (फंड, फंक्शन्स और फंक्शनरीस) प्रदान करके पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को सुदृढ़ किया गया। स्थानीय आयोजना, निर्णय लेने और पर्यवेक्षण में इन संस्थानों की उचित रूप से परिभाषित भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सत्ताईस विषय इन संस्थानों को स्थानांतरित किए गए।

- ख. पीआरआई के पहले स्तर के लिए चुनाव नवंबर, 2018 में और दूसरे स्तर के ब्लॉक विकास परिषदों (बीडीसी) के चुनाव नवंबर-दिसंबर, 2019 में हुए थे। 73<sup>वें</sup> संवैधानिक संशोधन के तहत अधिदेश के अनुसार एक कार्यात्मक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए जिला विकास परिषदों (डीडीसी) का गठन किया गया। जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार 280 डीडीसी निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे चुनाव कराए गए। 3991 सरपंच और 28521 पंच, 264 बीडीसी अध्यक्ष और 280 डीडीसी सदस्य चुने गए।
- ग. पंचायत चुनाव नहीं कराने के कारण 2016-17 से चौदहवें वित्त आयोग के तहत 1642.06 करोड़ रुपये की अनुदान प्रदान नहीं किया गया था। इन निधियों को अनलॉक किया गया और पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से 2019-20 में हल्का पंचायतों को जारी की गई। भागीदारी योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार की गईं। ये जीपीडीपी नियमित रूप से ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।
- घ. सभी पंचायती राज संस्थानों के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण कार्य किया गया और लगभग 6,000 निर्वाचित प्रतिनिधियों को अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेष्ठ परिपाटियों को सीखने के लिए एक्सपोजर-सह-प्रशिक्षण दौरों पर भेजा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति देने की शक्ति पंचायत स्तर पर पीआरआई को सौंपी गई। तीनों स्तरों के पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है।

## 5. सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना

- क. पुनर्गठन के बाद, जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने और उनकी जरूरतों को समझने के लिए जम्मू और कश्मीर में महत्वाकांक्षी बैक टू विलेज (बी2वी) कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब तक, 2018-19 से 2023-24 तक इस कार्यक्रम के पांच चरण आयोजित किए जा चुके हैं। प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, राजपत्रित अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों ने नियमित रूप से सभी 4291 पंचायतों का दौरा किया है और आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित पंचायतों में विस्तृत वार्ता की है। शिकायतों के

निवारण और स्थानीय विकास से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने के लिए सभी पंचायतों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

- ख. बी2वी कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में, पिछड़े ब्लॉकों के उत्थान के लिए "एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट" कार्यक्रम की अनूठी पहल शुरू की गई। विवेकपूर्ण ढंग से ब्लॉकों को चुना गया और ऐसे ब्लॉकों के त्वरित विकास के लिए 44 करोड़ रुपये (प्रति ब्लॉक 1 करोड़ रुपये) प्रदान किए गए। चयनित 285 पंचायतों (प्रति ब्लॉक एक पंचायत) के समग्र विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए " एस्पिरेशनल विलेज डेवलपमेंट" कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

## 6. सामाजिक न्याय के लिए कानूनी सुधार

- क. 2019 के संवैधानिक सुधारों से पहले, जम्मू और कश्मीर के लोग महत्वपूर्ण केंद्रीय कानूनों के लाभों से वंचित थे, यथा- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतीकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1954, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रीय विधान। 2019 के सुधारों के बाद, संविधान के सभी प्रावधान और सभी केंद्रीय अधिनियम संघ राज्य क्षेत्र पर लागू कर दिए गए हैं।
- ख. अगस्त, 2019 से पहले, समाज के कई वर्ग, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, सफाई-कर्मचारी और वाल्मिकी समाज के लोग, जो आजादी के बाद से ही जम्मू और कश्मीर में रह रहे थे, विधानसभा और पीआरआई चुनावों में वोट देने के हकदार नहीं थे। सुधारों ने इन वर्गों तक ऐसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों के विस्तार किया। इसके अलावा, समाज के महत्वपूर्ण वर्ग जैसे, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई-कर्मचारी और वाल्मिकी समाज, जम्मू और कश्मीर के बाहर विवाहित स्थानीय महिलाओं के बच्चे और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्ति अपने मूल अधिकारों से वंचित रह गए थे। 2019 के सुधारों ने जम्मू और कश्मीर के ऐसे निवासियों को अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने और सरकारी नौकरियों और ऐसे अन्य समान लाभों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बनने में मदद की।

- ग. सीधी भर्ती, पदोन्नति और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा और निकटवर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का विस्तार करने के लिए जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया।
- घ. सकारात्मक कार्रवाई के हिस्से के रूप में, पहाड़ी भाषी लोगों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण का विस्तार किया गया है। हाल ही में, संसद ने जम्मू और कश्मीर की "अन्य पिछड़ी जातियों" को देश के अन्य हिस्सों के अन्य पिछड़ी जातियों बराबर लाने के लिए जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है। हाल ही में, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करके पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र के कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित व्यक्तियों को नामांकन के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।
- ङ. इससे पहले, कोई भी राजनीतिक आरक्षण, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में सीटों का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं था। संविधान संशोधन और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमन के साथ, एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए विधान सभा में सीटें आरक्षित की गई हैं।

## 7. ई-गवर्नेंस पहल

- क. डिजिटल शासन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने भौतिक फाइलों के स्थान ई-ऑफिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की है। जिला स्तर तक 450 से अधिक सरकारी कार्यालयों ने ई-ऑफिस को अपनाया है। इससे सरकार को 150 साल पुराने दरबार स्थानांतरण को समाप्त करके प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिली।
- ख. शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के इस अभियान से यह सुनिश्चित हुआ है कि विभिन्न विभागों की कई प्रमुख सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। इससे नियमित सेवाओं और लाभों के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। जम्मू और कश्मीर ने 1100 से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन पेशकश करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और इस तरह इसने देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया और डिजिटल प्रशासन में नया मानक स्थापित किया।

- ग. जम्मू और कश्मीर ने राज्य पोर्टल और सेवा दोनों श्रेणियों में 2021 में राष्ट्रीय ई-सेवा प्रदान मूल्यांकन में संघ राज्य क्षेत्रों में पहला स्थान प्राप्त किया। मजबूत नागरिक फीडबैक तंत्र बनाया गया है और फीडबैक के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गईं। रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) से जुड़ी सेवाओं की अधिकतम संख्या के साथ जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों में अग्रणी स्थान पर है।
- घ. समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं को शामिल करने हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) में संशोधन किया गया। मोबाइल-दोस्त ऐप और डिजी-दोस्त पहल मोबाइल गवर्नेंस और सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी को सुविधाजनक बनाते हैं; जिससे डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिले। नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देने के लिए जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (JK-IGRAMS) बनाई गई। नागरिक इस पोर्टल पर शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं।
- ङ. संघ राज्य क्षेत्र में यह डिजिटल क्रांति सभी स्तरों पर शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है।

## 8. शासन में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार

- क. भू-प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पोर्टल बनाया गया। इससे नागरिक अपने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आज संघ राज्य क्षेत्र में 29 लाख भू-धारकों के पास अपनी भूमि पासबुक है जिसमें उनके स्वामित्व के तहत सभी भूखंडों का विवरण है। भू-राजस्व दस्तावेजों का पंजीकरण ऑनलाइन कर दिया गया है। पंजीकरण एक दिन के भीतर पूरा हो जाता है। 2019 से अब तक 2,53,083 पंजीकरण किए गए हैं और 1505.70 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।
- ख. सभी विकासात्मक कार्यों का विवरण एम्पावरमेंट/जनभागीदारी पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल पर नागरिक बिना किसी रूकावट के सभी चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में कार्यों की सार्वजनिक निगरानी से निर्माण लागत में कमी आई है और कार्य निष्पादन में तेजी आई है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने योजना विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से कार्यों का भौतिक सत्यापन शुरू करके विकास में जवाबदेही सुनिश्चित की। निष्पादन से पहले और

बाद के चरणों में जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ काम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन प्रूफ (ऑन-साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड) प्लेटफॉर्म शुरू किया गया।

- ग. अनुमोदन, बोली और निष्पादन प्रक्रियाओं में अनुशासन लाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र में सामान्य वित्तीय नियमावली शुरू की गई। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने बीईएमएस (बजट, आकलन, आवंटन और निगरानी प्रणाली) प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन के कार्य-वार आवंटन को सुनिश्चित करके वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए आईटी सुधार शुरू किए। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी प्रापण और लागत में बचत के लिए सभी स्तरों पर सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य की गई। संघ राज्य क्षेत्र सरकार को जीईएम आधारित खरीद में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ।

## 9. अवसंरचनात्मक विकास में तेजी लाना

- क. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने अवसंरचनात्मक विकास में तेजी लाने के लिए पूंजी को समझदारी से निवेश किया। चूंकि 2018-19 में कई परियोजनाएँ रुकी हुई थीं, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने उनकी आर्थिक संभावना और सामाजिक महत्व के आधार पर ऐसी लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी। प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए, सरकार ने तेज गति से वित्त प्रदान किया और 3218 करोड़ रुपये की लागत से 1632 परियोजनाएँ शुरू कीं।
- ख. प्रधान मंत्री के विकास पैकेज ने संघ राज्य क्षेत्र में अवसंरचनागत कमियों को पूरा करने में बड़ा समर्थन प्रदान किया है। इस पैकेज के अंतर्गत 53 परियोजनाओं के लिए 46,981 करोड़ रुपये जारी किए गए। दिसंबर, 2023 तक 45,448 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है और 33 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
- ग. **विद्युत क्षेत्र** - अपनी पनबिजली क्षमता का दोहन करने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 624 मेगावाट किरू, 850 मेगावाट रैटल, 1000 मेगावाट पाकल दुल और 540 मेगावाट क्वार परियोजनाओं के विकास के लिए एनएचपीसी के साथ समझौता किया। अब तक भारत सरकार ने किरू, क्वार और रैटल परियोजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र को इक्विटी योगदान हेतु 1300 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। स्थापित जल विद्युत क्षमता को 3500 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 6500 मेगावाट तक करके, सरकार का लक्ष्य प्राकृतिक लाभ का दोहन करना और अपनी बिजली खरीद लागत को कम करना है। इन परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। 3284 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 04 अन्य जलविद्युत परियोजनाओं,



अर्थात् सावलकोटे (1856 मेगावाट), दुलहस्ती चरण- II (258 मेगावाट), उरी- I चरण - II (240 मेगावाट), और किरथई - II (930 मेगावाट) के विकास के लिए एनएचपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इन परियोजनाओं से जम्मू और कश्मीर में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। संघ राज्य क्षेत्र को निःशुल्क बिजली में अपनी हिस्सेदारी, स्थिर बिजली की दीर्घकालिक आपूर्ति, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और रोजगार के अवसरों के सृजन से भी लाभ होगा।

- घ. पारेषण क्षेत्र में, 8 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण/संवर्द्धन करके 2019 से 220 केवी स्तर पर 1940 एमवीए क्षमता जोड़ी गई। 30 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण/संवर्द्धन करके 132 केवी स्तर पर 2080 एमवीए जोड़ा गया। 467 किमी नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गईं। वितरण क्षेत्र में, 266 उप-स्टेशनों का निर्माण/संवर्द्धन करके 66-33 केवी स्तर पर 1753 एमवीए क्षमता जोड़ी गई। कुल 10953 किलोमीटर नई एचटी और एलटी लाइनें बिछाई गईं। 9071 वितरण ट्रांसफार्मर का निर्माण/संवर्द्धन करके 11 केवी स्तर पर 1255 एमवीए क्षमता जोड़ी गई।
- ङ. स्वतन्त्रता के बाद पहली बार उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी को बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। 2019-2023 के दौरान पारेषण क्षमता में 150% के इस व्यापक विस्तार से दूर-दराज के गांवों में बिजली आपूर्ति करना और बहुत अधिक मांग को पूरा करना संभव हुआ है। घाटे को कम करने, राजस्व में सुधार करने और उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर नजर रखने की सुविधा देने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं जनवरी, 2024 तक 4.61 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
- च. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने लघु जलविद्युत परियोजनाओं और सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को विकसित करने के लिए अथक प्रयास किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जम्मू और श्रीनगर शहरों में छत पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को क्रियान्वित किया।
- छ. **सड़क और रेलवे** - जम्मू से श्रीनगर के बीच रेलवे लिंक का निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आशा है कि वर्ष 2024 में कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है।
- ज. सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के वित्तपोषण के माध्यम से सड़क नेटवर्क का भी विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया। पिछले चार वर्ष में पीएमजीएसवाई के तहत विभिन्न गांवों के लिए 7000 किमी से अधिक सड़कों का

निर्माण किया गया है। 2001 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी ग्रामीण बस्तियों को जोड़ा गया है, और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में शामिल शेष गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने का काम चल रहा है।

- झ. कड़ी निगरानी और त्वरित कार्य-निष्पादन के माध्यम से, सड़क निर्माण की गति दोगुनी हो गई है। जहां वर्ष 2017-20 के दौरान 2914 परियोजनाएं पूरी हुईं और 9382 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण किया गया, वहीं वर्ष 2020-23 के दौरान 7820 से अधिक परियोजनाएं पूरी हुईं और 17248 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण किया गया। इससे दूरदराज के गांवों तक सड़क संपर्क में काफी सुधार हुआ है और इस हिमालयी संघ राज्य क्षेत्र में यात्रा के समय में काफी कमी आई है।
- ञ. 3017 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 8.45 कि.मी. लंबी ट्विन ट्यूब काजीगुंड-बनिहाल सुरंग के निर्माण कर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के समुन्नयन से एक नई उपलब्धि प्राप्त की गई है। 4509 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर श्रीनगर-लेह सड़क पर 14.20 कि.मी. समानांतर निकास मार्ग के साथ 13.15 कि.मी. 2-लेन द्वि-दिशात्मक ज़ोजिला सुरंग पर काम चल रहा है।
- ट. 2379 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से श्रीनगर सोनमर्ग रोड पर 6.40 किमी जेड-मोड़ सुरंग पर काम चल रहा है। एनएच-244 पर सुधमहादेव-द्रांगा सुरंग। और ॥ (8 कि.मी.) की 3703 करोड़ रु. की परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा ईपीसी मोड आधार पर अनुमोदित किया गया था। 431.28 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर 1.574 कि.मी. की खेलानी बाईपास सुरंग पर काम शुरू किया गया है और वास्तविक प्रगति 70% है। चमोती से द्रबशला तक राष्ट्रीय राजमार्ग- 244 की 495 मीटर सुरंग पर भी काम चल रहा है।
- ठ. जम्मू के लिए सेमी-रिंग रोड (58 कि.मी.) का काम पूरा होने वाला है और लगभग 52 कि.मी. लंबे मार्ग का निर्माण किया जा चुका है। श्रीनगर के लिए 4-लेन सेमी-रिंग रोड पर काम जारी है और 39% काम (चरण-1) पूरा हो चुका है। 3685 करोड़ रु. की लागत से अखनूर-पुंछ सड़क को डबल लेन करने का काम शुरू किया गया है, जिससे पुंछ और राजौरी जिलों के लोगों को भरपूर लाभ होगा।
- ड. **सिंचाई और जल आपूर्ति** - पूरे संघ राज्य क्षेत्र में घरों में जल आपूर्ति संबंधी व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। सरकार ने बोरवेल और ट्यूबवेल के निर्माण, जल उपचार संयंत्रों को चालू करने, ओवरहेड टैंकों के निर्माण और पाइप नेटवर्क बिछाने में पूंजी निवेश किया। इससे जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्त पोषण के माध्यम से वर्ष 2019 से पहले कवर किए

गए 5.7 लाख से जनवरी 2024 तक लगभग 14.20 लाख ग्रामीण घरों तक घरेलू नल कनेक्शन का तेजी से विस्तार करने में मदद मिली।

- ढ. जम्मू की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक कृत्रिम झील के निर्माण की परिकल्पना करने वाली तवी बैराज परियोजना की पुनःशुरुआत 08 वर्षों के बाद की गई है। परियोजना निष्पादन पूरे जोरों पर है और 64.80 करोड़ रु. की लागत से पूरा होने की संभावना है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर काम सही मायने में शुरू किया गया है। इससे जम्मू और कश्मीर के लिए रावी नदी से 1150 क्यूसेक पानी का उचित हिस्सा प्राप्त करने और एक लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- ण. झेलम नदी और इसकी सहायक नदियों (चरण-1) का बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम पूरा हो गया है, जिससे झेलम की वहन क्षमता 31800 क्यूसेक से बढ़कर संगम स्थल पर 41000 क्यूसेक हो गई है। झेलम नदी में बाढ़ के आकलन के बाद, विश्व बैंक से 250 मिलियन अमरीकी डालर की रियायती सहायता से 213 परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें से 175 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और 38 परियोजनाओं को सक्रिय रूप से निष्पादित किया जा रहा है। परियोजना व्यय संचयी रूप से 1320 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
- त. **शहरी विकास और आवास** - सैटेलाइट शहरों में आवासीय अवसंरचना का नियोजित विकास चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आवास कॉलोनियां और नई टाउनशिप कोट भलवाल, चटरहमा, और गुंड अक्सा में स्थापित की जा रही हैं। स्मार्ट गतिशीलता, डिजिटल शासन और सतत विकास के प्रयासों ने जम्मू और श्रीनगर को संघ राज्य क्षेत्र के अन्य शहरों के लिए शहरी परिवर्तन का एक नया मॉडल बना दिया है।
- थ. किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) कार्यक्रम के अंतर्गत, सुंजवान, जम्मू में किफायती घर पूरे किए गए और 2 अगस्त, 2023 को पात्र लाभार्थियों को सौंप दिए गए। सरकार ने अमृत वित्त-पोषण के माध्यम से विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कई अवसंरचना परियोजनाएं पूरी कीं।
- द. स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत, जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में शहरी अवसंरचना और सेवाओं में सुधार देखा गया। योजनाबद्ध वित्त-पोषण को कंवर्जेंस निधि के साथ जोड़कर और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर, सरकार शहरी अवसंरचना में सुधार के लिए निजी क्षेत्र का वित्त जुटाने में सफल रही। हरित शहरी परिवहन की दिशा में आगे बढ़ते हुए, सरकार परिचालन तथा बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव में दक्षता और अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ, दोनों राजधानी शहरों में 150 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) चला रही है।

## 10. **आर्थिक क्षमता खोलना**

- क. **कृषि और संबद्ध क्षेत्र** - ग्रामीण आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानते हुए, संघ राज्य क्षेत्र सरकार सभी कृषि भूमि को दो-फसल पद्धति के अधीन लाने

की दिशा में काम कर रही है। शीत भंडारण क्षमता को वर्ष 2018 में 1.133 लाख मीट्रिक टन से 68% बढ़ाकर वर्ष 2022 में 1.910 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र मार्च 2024 तक 2 लाख मीट्रिक टन क्षमता का आंकड़ा पार कर जाएगा। किसान परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, कुल अब तक 14.83 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बांटे जा चुके हैं।

- ख. उच्च घनत्व वाले फलों के बागान के तहत अब 12000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को जोड़ा गया है। इससे सेब उत्पादकों की आय में काफी वृद्धि होगी। सरकार 'परवाज़' स्कीम के अधीन चिह्नित खराब होने वाले फलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त बाजार संपर्क और हवाई परिवहन भी प्रदान कर रही है। कुल 23 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के साथ एकीकृत किया गया है।
- ग. संघ राज्य क्षेत्र सरकार मशीनीकरण, उच्च घनत्व वृक्षारोपण, शीत भंडारण और किसान बीमा में दृढ़ता से निवेश करके कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए निवेश कर रही है। इस प्रकार, सरकार ने 5013 करोड़ रु. के आवंटन के साथ "समग्र कृषि विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 29 कार्यक्रम शुरू किए।
- घ. इस कार्यक्रम से अगले पांच वर्षों के भीतर इन क्षेत्रों में मूल्यवर्धन को दोगुना करने, क्षेत्रीय विकास दर को 11% तक बढ़ाने, 2.87 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और लगभग 19000 उद्यम स्थापित करने की आशा है।
- ङ. **ग्रामीण विकास** - जम्मू और कश्मीर को कृषि परिवारों की मासिक आय में तीसरा तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पांचवां सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र ने प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों के निर्माण में देश में तीसरी रैंकिंग हासिल की। संघ राज्य क्षेत्र में 3336 अमृत सरोवर पूरे किए गए, जो स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं तथा कृषि और घरेलू उद्देश्यों के लिए जल संसाधनों को बढ़ा रहे हैं।
- च. आवास सह पीएमएवाई-जी (प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण) लाभार्थियों के अधीन 469 भूमिहीन परिवारों को 5 मरला भूमि आवंटित की गई है। सालाना बनने वाले घरों की संख्या वर्ष 2022-23 में चौगुनी होकर 51290 हो गई और जनवरी 2024 तक 47100 को पार कर गई। मनरेगा के अंतर्गत वार्षिक निर्माण-कार्यों की संख्या भी वर्ष 2019-20 में 54,315 से चौगुनी होकर जनवरी 2024 तक 200,000 से अधिक हो गई।

- छ. **पर्यटन** - पर्यटन विभाग ने पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सेवाओं में सुधार तथा पर्यटक आकर्षणों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में निवेश किया। संघ राज्य क्षेत्र ने उस समय विश्व ख्याति अर्जित की जब उसने 22 से 24 मई, 2023 तक श्रीनगर में जी20 देशों की पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की। यह आयोजन जम्मू-कश्मीर में पर्यटन की प्रगति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।
- ज. बढ़ती पर्यटकों के प्रवाह को समायोजित करने और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने होम-स्टे दिशा-निर्देश तैयार किए। 13,000 की बिस्तर क्षमता वाले 1485 से अधिक घरों को अब तक पंजीकृत किया गया है। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के बाद, इस क्षेत्र में निवेश में भारी वृद्धि देखी गई है। पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने और समान लाभ साझा करना सुनिश्चित करने की दिशा में पहल किए जा रहे हैं। इस पहल ने संघ राज्य क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को असाधारण रूप से बेहतर बनाने में सहायता की। इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, जिसमें 2022 में 1.88 करोड़ से अधिक पर्यटक जम्मू-कश्मीर आए और 2023 में पर्यटकों की संख्या 2.11 करोड़ रही।

## 11. औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाना

- क. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने नए निवेश को आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का विस्तार करने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 का शुभारंभ किया। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30, निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30, ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प एवं हथकरघा नीति 2020 अधिसूचित की गई है।
- ख. मौजूदा 64 औद्योगिक एस्टेट के अतिरिक्त, 'मेड इन जम्मू एंड कश्मीर' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 46 एस्टेट का विकास किया जा रहा है। 90182 करोड़ रु. के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें 4,01,965 युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता है। वर्ष 2019-20 से 5319 करोड़ रु. का निवेश आया है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्टार्ट-अप नीति को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिल्प उद्योग को नई गति प्रदान करने के लिए करखांदर स्कीम लागू की जा रही है।

- ग. 2022 निर्यात रैंकिंग में जम्मू और कश्मीर भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले संघ राज्य क्षेत्र के रूप में उभरा है। संघ राज्य क्षेत्र ने अपनी रैंकिंग वर्ष 2020 में 35 से सुधारकर वर्ष 2022 में 17 कर ली है। हथकरघा और हस्तशिल्प का निर्यात वर्ष 2021-22 में 563 करोड़ रु. से दोगुना होकर वर्ष 2022-23 में 1116 करोड़ रु. हो गया है।

## 12. रोजगार के अवसरों का विस्तार

- क. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 2019 के सुधारों के बाद बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया। अगस्त 2019 से अब तक 31,830 चयन निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित तरीके से किए गए हैं। वेतन स्तर -5 तक के पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न पदों के लिए 12,264 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं।
- ख. स्व-रोजगार योजनाओं और बैंकों से वित्तीय सहायता के माध्यम से भी रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया गया। मिशन यूथ पहल के अंतर्गत, मुमकिन, तेजस्वनी, स्परिंग एंटरप्रेन्योर कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी संख्या में युवा और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- ग. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, ई-श्रम पोर्टल पर 34 लाख से अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ इस क्षेत्र के सभी श्रमिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
- घ. संघ राज्य क्षेत्र सरकार सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए गहनता से काम कर रही है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने तथा किसानों और सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले ऋण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, 537 पीएसीएस को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पंचायत में एक अनुमोदित पीएसीएस बनाना है जो समावेशी रूप से संचालित हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायता दे।
- ड. कारीगरों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम 7% की आकर्षक ब्याज छूट के साथ लागू की जा रही है। सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और खाद्य उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। ऋण विस्तार के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/एफपीओ की संख्या बढ़ाई जा रही है।

### 13. जीवन को बेहतर बनाना

- क. **स्वास्थ्य** - जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सभी निवासियों को निःशुल्क 5 लाख रु. प्रति परिवार का सर्व स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए देश में सेहत (स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन पहल के लिए सामाजिक प्रयास), सर्व स्वास्थ्य बीमा योजना, शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानदंड से आगे बढ़ते हुए, सेहत स्कीम के अधीन कवरेज को पूरे संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित कर दिया गया। 83.50 लाख से अधिक व्यक्तियों को सेहत गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए लगभग 229 अस्पताल एबी-पीएमजेएवाई/सेहत स्कीम के तहत सूचीबद्ध हैं। अब तक लगभग 10.70 लाख उपचार प्रदान किए गए हैं जिससे रोगियों के लिए 1844 करोड़ रु. के जेब खर्च में कमी आई है। इस पहल के लिए संघ राज्य क्षेत्र को प्रधानमंत्री का पुरस्कार मिला।
- ख. संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने वर्ष 2019 से 3000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू किए हैं। जन औषधि केंद्रों को वर्ष 2019 में 38 से बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक 270 कर दिया गया है। आपातकालीन देखभाल के लिए 480 से अधिक नई एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत कवरेज को व्यापक बनाया गया है। इन उपायों से संघ राज्य क्षेत्र को आईएमआर 2019-20 में 22.0 से घटाकर 2023-24 में 16.3 करने में मदद मिली है, साथ ही जन्म के समय लिंग अनुपात वर्ष 2019-20 में 927 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 976 हो गया है।
- ग. नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना से चिकित्सा शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। पिछले चार वर्षों के भीतर एमबीबीएस, स्नातकोत्तर और नर्सिंग शिक्षा में लगभग 4500 सीटें जोड़ी गई हैं। 07 नये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चालू एवं संचालित किए गए हैं। 28 बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय (निजी सहित) और 19 बीएससी पैरामेडिक महाविद्यालय (निजी सहित) जोड़े गए हैं।
- घ. **शिक्षा** - मानव जीवन के पहले 5 वर्षों में उचित पोषण और शिक्षा को प्रायः सबसे महत्वपूर्ण निवेश माना जाता है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 15000 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों का विकास

शुरू करके प्रारंभिक बाल्य शिक्षा प्रदान करने की पहल का शुभारंभ किया है। वर्ष 2019 के बाद से संघ राज्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण से प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है, वर्ष 2019-20 में नामांकन 12.4 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 15 लाख से अधिक हो गया है। लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। सभी विद्यालयों में चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली शुरू करके शिक्षण कर्मचारियों की समय की पाबंदी और कामकाजी अनुशासन को बढ़ाया गया।

ड. संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 2019 के बाद से 51 नए डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना के साथ उच्च शिक्षा में तेजी देखी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 लागू की गई और संघ राज्य क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों में चार साल के स्नातक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 66 महाविद्यालयों को प्रतिष्ठित एनएएसी मान्यता प्राप्त हुई। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50 विषयों की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का विकास किया गया है और अपलोड किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने शिक्षकों और संस्थानों के मूल्यांकन के लिए अद्वितीय फीडबैक पोर्टल की स्थापना की। सीयूईटी (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) स्कोर के आधार पर केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया ई-समर्थ पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) वित्त पोषण के अंतर्गत परियोजनाओं के माध्यम से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अवसंरचना को काफी बढ़ावा मिला। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों को भूमि और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके कार्यात्मक बनाया गया।

च. **खेल** – वर्ष 2019 के सुधारों से जम्मू और कश्मीर में खेल क्रांति का शुभारंभ हुआ है। 702 खेल परियोजनाओं के पूरा होने, 100 खेलो इंडिया केंद्रों के निर्माण और पूरे संघ राज्य क्षेत्र में इनडोर खेल परिसरों के विकास के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र में खेलों का पूर्ण पुनरूत्थान हुआ है। लगभग हर जिले में बहुउद्देशीय इनडोर खेल हॉल का निर्माण किया गया है। हर पंचायत में खेल के मैदान विकसित किए गए हैं। कई स्टेडियमों में फ्लडलाइटिंग और सिंथेटिक टर्फिंग लगाई जा रही है।

छ. जम्मू और श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में कैनोइंग, रोइंग और फेंसिंग में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। सिंथेटिक हॉकी टर्फ, केके हक्कू स्टेडियम, जम्मू और सिंथेटिक हॉकी टर्फ, पोलोग्राउंड, श्रीनगर का निर्माण और अनुमोदन भारतीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) द्वारा किया गया था। खेल गांव, नगरोटा में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ विकसित किया जा रहा है।



#### 14. वित्तीय समावेश का आश्वासन

- क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 3000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गांवों में भौतिक शाखाएं स्थापित करने को प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता वाले 167 गांवों में से 162 गांवों को बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट या भौतिक शाखाओं के माध्यम से कवर किया गया है। अनुसूचित बैंकों के समन्वय से वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया गया है।
- ख) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिसंबर 2023 तक 1,84,681 लाभार्थियों को 4348 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। 7.50 लाख केसीसी (फसल) खाताधारकों को 5880 करोड़ रुपये और 1.72 लाख केसीसी-एएचएफ (पशुपालन और मत्स्य पालन) खाताधारकों को 1296 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। पीएम-स्वनिधि योजना के तहत, 23100 से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी के साथ विशेष ऋण सुविधा वितरित की गई है।
- ग) जेएंडके बैंक की प्रवर्तक होने के नाते, यूटी सरकार ने इसकी पूंजी पर्याप्तता और कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रयास किया। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने सत्ता के संकेंद्रण को सीमित करने, बोर्ड और प्रबंधन को पेशेवर बनाने के लिए सुधारों में मदद की। कोविड-19 के प्रभाव और उसके परिणामस्वरूप उच्च एनपीए के कारण बैंकों को नुकसान हुआ, तो संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 2019 से 2022 तक पर्याप्त इक्विटी पूंजी डालकर बैंक को मजबूत किया। इन कदमों ने बैंक की वित्तीय सेहत को रूपांतरित करने में मदद की और इसके बिजनेस के विकास और 2019 से पहले की अवधि के घाटे से बाहर निकलने में सक्षम बनाया। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने कोविड महामारी के आर्थिक झटके से निपटने के लिए ब्याज छूट योजना भी शुरू की। इसने कई व्यावसायिक उद्यमों को बैंकिंग क्षेत्र के संरक्षण और सुरक्षा में सक्षम बनाया।

#### 15. सामाजिक समावेश का विस्तार

- क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अपने सामाजिक सुरक्षा कवर को दोगुना कर दिया है। मासिक सहायता/पेंशन लाभ को 2014-15 में लगभग 5.0 लाख लाभार्थियों से बढ़ाकर 2022-23 में लगभग 8.5 लाख कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र ने समाज कल्याण विभाग के पास पंजीकृत सभी पात्र

लाभार्थियों को पेंशन लाभ प्रदान करके योजना में पूर्णता हासिल की। विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए, सरकार ने मोटर चालित तिपहिया साइकिलें प्रदान की हैं।

- ख) योग्यता सह साधन अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, सरकार ने 1,43,154 (2018-19) से 2022-23 में 3,00,651 छात्रों तक कवरेज में 210% की वृद्धि सुनिश्चित की। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाओं के कवरेज में 169% की वृद्धि हुई है, जिसमें 2018-19 में 8,250 के मुकाबले 2022-23 में 63,550 छात्रों का कवरेज हुआ है।
- ग) जनजातीय कार्य विभाग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, अवसंरचना विकास और आजीविका के क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। प्रवासी जनजातीय समुदायों को ट्रांजिट सुविधाएं प्रदान की गईं। 8 नये छात्रावास भवन, 200 स्मार्ट स्कूल, 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय विकसित किए गए। विभाग ने 2000 आदिवासी युवाओं को विशिष्ट कोचिंग सुविधाएं, कौशल विकास और 46,000 आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की।

## 16. महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना

- क) "लाडली बेटी" और "राज्य विवाह सहायता योजना" जैसी पहल समाज में महिलाओं का आदर-सम्मान वापस ला रही है। यूटी-प्रायोजित योजना "लाडली बेटी" के तहत, सरकार ने कवरेज को 2017 में 16095 मामलों से बढ़ाते हुए 2022-23 में 1, 03, 294 मामलों तक कर दिया। इस अवधि में योग्य बालिकाओं के लिए वित्तीय सहायता 3 करोड़ रु. से बढ़ाकर 150 करोड़ रु. कर दी गई।
- ख) विवाह सहायता के लिए एक अन्य यूटी-प्रायोजित योजना के तहत, 2015-16 से 2021-22 तक 62,326 गरीब लड़कियों को 185 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 2022-23 के दौरान इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया गया, 16,000 गरीब लड़कियों को विवाह के लिए 80 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- ग) ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों के महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं। 87,541 स्वयं सहायता समूहों से सात लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। लगभग तीन लाख महिला किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। महिला किसानों ने अपने परिवारों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग दो लाख कृषि पोषण उद्यान स्थापित किए

हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन ने पिछले एक साल में 10,000 माइक्रो-स्टार्टअप शुरू किए हैं।

घ) संसद द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया है, जो जम्मू और कश्मीर विधान सभा में महिलाओं के लिए सभी निर्वाचित सीटों में से एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है।

## 17. 2023-24 में अर्थव्यवस्था की स्थिति

क) वर्तमान वित्त वर्ष (2023-24) के लिए जीएसडीपी वृद्धि 7.5% होने की आशा के साथ जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था विकास पर है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विकासात्मक पहलों को बनाए रखने के लिए, सरकार ने कर और गैर-कर उपायों को विवेकपूर्वक इस्तेमाल किया है।

ख) जीएसटी के तहत डीलर पंजीकरण को 2018 में लगभग 72,000 से बढ़ाकर 2023 में 1,97,000 कर दिया गया है। केंद्रित प्रवर्तन और डीलर आउटरीच ड्राइव शुरू की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सहयोग से कराधान कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का कार्य किया गया। जीएसटी लीकेज को रोकने के उद्देश्य से, खरीद पर नज़र रखने के लिए तंत्र विकसित किया गया। पूंजीगत कार्यों के तहत जीएसटी कटौती पर नज़र रखने और कर वसूली में सुधार के लिए, जीएसटीएन सत्यापन को बिल भुगतान प्रणाली से जोड़ा गया है।

ग) एनआईसी के सहयोग से, यूटी ने दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए ई-स्टाम्पिंग प्रणाली शुरू की। इससे स्टाम्प और पंजीकरण राजस्व 2018-19 में 190 करोड़ रु. से बढ़कर 2022-23 में 486 करोड़ रुपये हो गया। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने नई आबकारी नीति अधिसूचित की है और शराब की दुकानों के आवंटन में नीलामी की एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित की है। आपूर्ति श्रृंखला पर नज़र रखने और उत्पाद शुल्क राजस्व बढ़ाने के लिए ई-आबगरी प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है। इन उपायों ने जीएसटी, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प से राजस्व को स्वस्थ वृद्धि दर्ज करने में सक्षम बनाया है।

घ) वस्तु एवं सेवा कर के तहत राजस्व संग्रह 2023-24 ( दिसंबर, 2023 तक ) में 6,018 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2022-23 की समान अवधि में ऐसे राजस्व पर 10.60 प्रतिशत की वृद्धि का उदाहरण है। मोटर स्पिरिट टैक्स से राजस्व 2022-23 की समान अवधि में 1,185 करोड़ रुपये की प्राप्ति के मुकाबले 2023-24 (दिसंबर, 2023 तक) में 1240 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। स्टाम्प राजस्व 2022-23 के अन्तर्गत 379 करोड़ रुपये के मुकाबले दिसंबर,

2023 तक बढ़कर 416 करोड़ रुपये हो गया है, जो 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दिसंबर, 2023 के अंत तक उत्पाद शुल्क संग्रह 1758 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि 2022-23 के दौरान इसी अवधि में यह 1,392 करोड़ रुपये था, जिसमें 26% की वृद्धि दर्ज की गई।

ड) कुल कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि और लचीलापन दिखा है। बिजली की खपत पर नजर रखने के लिए एरियल बंचिंग केबल और स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया। 4.6 लाख मीटरों की स्थापना से उपभोक्ता व्यवहार पर असर पड़ा है और बिजली की खपत सीमित हुई है तथा 2023-24 में टैरिफ राजस्व में भी लगभग 10% का सुधार हुआ है। इन उपायों ने संघ राज्य क्षेत्र सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में कई उपलिब्धियां हासिल करने में सक्षम बनाया।

## 18. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का लाभ उठाना

क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने सभी व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं को पूर्ण करने और लाभार्थियों के लिए 100% आधार सीडिंग सुनिश्चित करने के लिए मेहनत से काम किया। जनवरी 2024 तक 50 से अधिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आधारित कल्याण योजनाओं (नकद और वस्तु दोनों) के माध्यम से 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को 3000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया गया है।

ख) जम्मू और कश्मीर में पिछले वर्ष 74 करोड़ 42 लाख ई-लेन-देन दर्ज किए गए, औसतन प्रतिदिन 2 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन दर्ज किए गए, जो कई विकसित राज्यों से अधिक है। राशन आपूर्ति और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अयोग्य लाभार्थियों को बाहर करने के लिए व्यवस्थित अभियान चलाया गया है।

ग) सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए व्यवस्थित रूप से आधार-सीडिंग की गई है। बायो-मीट्रिक सत्यापन और ई-पीओएस मशीनों के प्रावधान के माध्यम से राशन आपूर्ति में डीबीटी एवं आधार आधारित सत्यापन से लगभग 230 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसी तरह, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत डीबीटी का लाभ उठाकर 200 करोड़ रुपये से अधिक की बचत का लक्ष्य है।

## 19. बजट 2024-25

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,18,728 करोड़ रुपये का बजट अनुमान है, जिसमें अर्थोपाय संबंधी अग्रिमों का प्रावधान शामिल नहीं है। जहां राजस्व व्यय 80,162 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, वहीं पूंजीगत व्यय 38,566 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

20. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस सदन के समक्ष 2023-24 में संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्राप्त क्षेत्रवार विकास लक्ष्यों को गिनाती हूँ।

## 21 आर्थिक क्षेत्र

### 21.1 कृषि और संबद्ध क्षेत्र:

- क) पीएम फसल बीमा योजना को इस वर्ष सभी 20 जिलों तक पहुंचाया गया। केसर, मुश्कबुदजी चावल, भद्रवा राजमा, सोलाई शहद और बासमती चावल के लिए भौगोलिक चिह्न (जीआई) टैग प्राप्त किया गया है। इससे बेहतर उत्पाद पहचान और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित होगा और उत्पादकों को बेहतर रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा, कश्मीरी लाल मिर्च, काला ज़ीरा और लाल चावल जैसे अद्वितीय कृषि उत्पादों की जीआई टैगिंग के लिए महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किया गया।
- ख) सघन फल बागान के तहत लगभग 2500 हेक्टेयर क्षेत्र जोड़ा गया जिसमें उपोष्णकटिबंधीय फलों के लिए 2400 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। सुनिश्चित सिंचाई के लिए जल संचयन टैंक (डब्ल्यूएचटी)/सामुदायिक टैंक, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और बोरवेल स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, 83 बोरवेलों का निर्माण किया गया, जिससे सिंचाई के तहत लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र जुड़ गया।
- ग) फसल सघनता बढ़ाने और ज्यादा इलाकों को दोहरी फसल के अंतर्गत लाने के लिए मुश्कबुदजी चावल, कालाजीरा, भद्रवा राजमा आदि जैसी विशेष फसलें उगाने के लिए गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चेरी, स्ट्रॉबेरी, प्लम, नाशपाती आदि जैसी जल्दी खराब होने वाली फलों की फसलों को यूटी/देश के बाहर ले जाने के लिए बागान मालिकों को हवाई परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है।
- घ) समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के तहत, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नर्सरी स्थापित की जा रही हैं। बडेड/ग्राफ्टेड अखरोट के पौधों के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र में छह (06) अखरोट नर्सरी स्थापित की जा रही हैं। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री को बढ़ाने और उनके उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र के तहत चार (04) नर्सरियों को 58,000 एप्पल क्लोनल रूटस्टॉक प्रदान किए गए।
- ङ) लगभग 60,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले 12 कोल्ड स्टोरेज चालू किए गए। नरवाल, जम्मू में 2,000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर और मजबुग, सोपोर में 2,500 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोर नाबार्ड ऋण के तहत स्वीकृत किया गया और इन परियोजनाओं के मार्च 2024 में पूरा होने की संभावना है।

च) 2023-24 के दौरान सब्जियों की खेती के तहत 11,000 हेक्टेयर भूमि जोड़ी गई। जम्मू और कश्मीर में जल-जमाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरी भूमि को खेती योग्य बना दिया गया है, जिससे संघ राज्य क्षेत्र में पीली क्रांति की शुरुआत हुई है। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2852 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।

**वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए पूंजीगत व्यय के तहत 2029.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 500.89 करोड़ रुपये अधिक है।**

## 21.2 ग्रामीण विकास:

क) जम्मू और कश्मीर के सभी गांवों को अगस्त 2023 में ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा मिल गया है। 2023-24 के दौरान, दिसंबर, 2023 तक 25,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 563 सामुदायिक स्वच्छता केंद्रों का निर्माण किया गया। 2023-24 के दौरान, दिसंबर 2023 के अंत तक 10,200 और एसएचजी का गठन किया गया है। मनरेगा के तहत 2023-24 में 200 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के मुकाबले 182.69 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं।

ख) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 396 पंचायत घरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। 1084 पंचायत घरों में, बीएसएनएल, वीसैट, स्वान आदि के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 2023-24 (दिसंबर 2023 तक) में 47,138 घरों का निर्माण किया गया है, जिससे पीएमएवाई (जी) की शुरुआत के बाद से 1,75,273 घरों के निर्माण की संचयी उपलब्धि हासिल हुई है।

ग) ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों (आरआरबी) को खराब वित्तीय स्थिति और उच्च स्थापना लागत के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उनमें सुधार लाने के लिए उनके प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखी गई। दोनों आरआरबी को 2023-24 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा 42 करोड़ रुपये का प्रोफेशनल नेतृत्व और पुनर्पूँजीकरण सहयोग प्रदान किया गया है। इससे प्रायोजक बैंकों और केंद्र सरकार से 350 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी।

**ग्रामीण क्षेत्र में, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत 3730.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।**

### 21.3 पर्यटन:

- क) जम्मू और कश्मीर ने 75 ऑफ-बीट पर्यटन स्थलों की पहचान की, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विकसित और प्रचारित किया जा रहा है। कश्मीर में 10 पर्यटन स्थलों और जम्मू संभाग में 10 पर्यटन स्थलों के लिए मूलभूत सुविधाओं हेतु वित्तपोषण का निर्धारण किया गया है। 75 विरासत स्थलों की पहचान की गई है और वास्तुशिल्प तथा विरासत के पुनरुद्धार, पुनर्स्थापन, संरक्षण और रखरखाव के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है।
- ख) इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई जब 2022 में 1.88 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर की यात्रा की। यह सकारात्मक प्रवृत्ति वर्ष 2023 के दौरान रिकॉर्ड 2.11 करोड़ पर्यटकों के आगमन के साथ जारी रही है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के अलावा, पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर के नए पर्यटन स्थलों की भी यात्रा की। नए पर्यटन स्थल पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से अपनी जगह बना रहे हैं। इस प्रकार 2023 में, शिव खोरी में 20 लाख, मानसर-सुरिसर में 10.5 लाख, पटनीटॉप में 10 लाख, दूधपथरी में 10 लाख और लोलाब में 1.5 लाख पर्यटक आए।
- ग) विदेशी पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना की वृद्धि हुई। ऑफ-बीट पर्यटन स्थलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग गंडोला ने 10 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया और 2023-24 के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया। अमरनाथजी की पवित्र गुफा तक जाने वाले मौजूदा मार्गों के जीर्णोद्धार और सुधार का कार्य सीमा सड़क संगठन के माध्यम से किया गया है। इस कार्य से तीर्थयात्रियों के लिए पहुंच, सुरक्षा और सुविधा में काफी सुधार हुआ है और स्थानीय पर्यटन को नया जीवन मिला है।
- घ) सोनमर्ग में इको-मोबिलिटी सुविधा शुरू की गई। विस्टा डोम कोच वाली स्पेशल ट्रेन शुरू की गई। विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 कार्यक्रम/उत्सव और 32 रोड शो आयोजित किए हैं, जिनमें दुबई, स्पेन और फ्रांस में प्रचार कार्यक्रम भी शामिल हैं। जम्मू संभाग में, विभाग ने कई सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया, जिनमें लोहड़ी उत्सव, बैसाखी उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, नवरात्र उत्सव, झिरी मेला, मेला बाहु किला, कैलाश यात्रा, सरथल यात्रा, मचैल यात्रा, बाबा चमलियाल मेला, बाबा सिदगोरिया मेला और कौंसर नाग यात्रा शामिल हैं। इसी तरह, कश्मीर संभाग में, टीटवाल कुपवाड़ा में सीमा पर्यटन उत्सव, गुरेज़ उत्सव, बांदीपोरा में केट्सन उत्सव, तंगमर्ग और मुंडागी में बदरकुट उत्सव और बारामूला में पाज़लपोरा उत्सव की व्यापक रूप से सराहना की गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक और पाक-कला विरासत को प्रदर्शित करने के

लिए कश्मीर के विभिन्न जिलों में 3-दिवसीय सूफी उत्सव, डाउनटाउन विरासत यात्रा और पारंपरिक खाद्य उत्सव का आयोजन किया।

- ड.) 2023 में संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 102 फिल्मों / वेब श्रृंखला की शूटिंग की गई। वुलर और मानसबल दोनों झीलों में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को शुरू करने के लिए वुलर झील में बोट क्लब-सह-जल खेल केंद्र को उन्नत किया जा रहा है। डल झील में ज़ोरबिंग, पेडल बोटिंग और जेट स्कीइंग की शुरुआत की गई है। जम्मू संभाग में मानसर झील और रणजीत सागर बांध पर भी जल क्रीड़ा गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। बालटाल, चंदनवाड़ी और टीटवाल जैसे रणनीतिक स्थानों पर पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। विशेष रूप से बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुरेज़ में पर्यटक सूचना केंद्र सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। श्री अमरनाथ जी यात्रियों को उनकी तीर्थयात्रा के दौरान सहायता के लिए चंदनवारी और बालटाल दोनों स्थानों पर मौसमी सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं।

**पर्यटन क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 357.70 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो कि 2023-24 के संशोधित आवंटन की तुलना में 103.95 करोड़ अधिक है।**

#### **21.4 वानिकी एवं पर्यावरण :**

- क) जम्बू चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया और 2023-24 में इसका संचालन शुरू हुआ। आज की तिथि में यूटी में 22,000 से अधिक इको-क्लब पंजीकृत हो चुके हैं। अब तक 6722 वन मित्र और 25265 पर्यावरण मित्रों को सूचीबद्ध किया गया है। विभाग ने पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इको-क्लबों को शामिल करते हुए 268 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
- ख) विभाग ने 515 जल संचयन प्रणाली, 7469 क्रेट्स और 86710 क्यूविक मीटर नाला पत्थर चेक बांधों के माध्यम से भूजल का पुनर्भरण करके वन क्षेत्रों में तालाबों का कायाकल्प किया है। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने 99.76 लाख वृक्षारोपण और 94.24 लाख कम लागत वाले हरित उपाय सुनिश्चित किए हैं।
- ग) दिसंबर 2023 तक 3971 ग्राम पंचायतों को "हर गांव हरियाली" वृक्षारोपण अभियान के तहत कवर किया गया है। शेष ग्राम पंचायतों को मार्च 2024 तक शीतकालीन वृक्षारोपण सीजन के दौरान कवर किया जाएगा। 4349 गांवों को "एक बीट गार्ड, एक गांव" कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है। 2023-24 के दौरान जंगलों के बाहर की भूमि को हरा-भरा



करने के लिए ग्राम पंचायतों को गाँव की सामान्य भूमि, कछारी और अन्य बंजर भूमि पर वृक्षों के रोपण के लिए मुफ्त पौधे और अन्य रोपण सामग्री प्रदान की गई है।

- घ) वन/संरक्षित क्षेत्रों में 135 आर्द्रभूमियों को साफ और बहाल किया गया है। घराना, होकरसर और शालबुघ जैसी आर्द्रभूमियों का जीर्णोद्धार डी-सिल्टिंग, डी-वीडिंग और सीमा निर्धारण के माध्यम से किया जा रहा है। वन (संरक्षण) नियम, 2022 में की गई परिकल्पना के अनुसार अनापत्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया के संचालन के लिए कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए परिवेश 2.0 लॉन्च किया गया।
- ड.) संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने प्रामाणिक व्यक्तियों के वन अधिकारों को प्रमुखता से मान्यता प्रदान करके संयुक्त वन प्रबंधन को मजबूत किया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पात्र वन निवासी समुदायों को 5053 सामुदायिक वन अधिकार और 352 व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदान किए गए हैं।

**वन क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 156.45 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है जो कि 2023-24 के संशोधित आवंटन से 22 करोड़ रुपये अधिक है।**

## **21.5 सहकारिता क्षेत्र:**

- क) जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए उनके प्रदर्शन पर बारीकी से नज़र रखी गई। अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (एसीसीबी) और जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (जेसीसीबी) ने तीन दशकों की अवधि के बाद वर्ष 2023 में परिचालन लाभ दर्ज किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के संबंध में JCCB के ट्रांजिशन के लिए नियुक्त किया गया है
- ख) 8764 सहकारी समितियों/सहकारिताओं का डेटा डिजिटल किया गया है। बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए कारीगरों/कारीगर सहकारी समितियों के सदस्यों को कारीगर कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला और बडगाम के सहकारी सुपर बाज़ारों को नया रूप देकर, बारकोड स्कैनिंग/बिलिंग मशीनें, डिजिटल डिस्ट्रे बोर्ड आदि शुरू करके आधुनिक बनाया गया है।

सहकारी क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 25 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है जो कि 2023-24 के संशोधित आवंटन से 5 करोड़ रुपये अधिक है।

## 22. सामाजिक क्षेत्र

### 22.1 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा:

- क) इस वर्ष हंदवाड़ा और उधमपुर में दो नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। इस कार्यान्वयन से यूटी में एमबीबीएस सीटें 200 तक बढ़ गई हैं। जिला बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा को टीबी मुक्त जिलों ( कुलगाम और शोपियां के राजस्व जिलों के साथ) के रूप में प्रमाणित किया गया है। जिला श्रीनगर और कुपवाड़ा को टीबी मुक्त जिलों (राजस्व जिला गांदरबल के साथ) के लिए गोल्ड अवार्ड मिला है। जिला बारामूला, उधमपुर, कठुआ और जम्मू (बांदीपुरा, रियासी और सांबा के राजस्व जिलों के साथ) को कांस्य पुरस्कार मिला है। पहली लाइव रोबोटिक सर्जरी इस वर्ष सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) श्रीनगर में आयोजित की गई। जम्मू में कैंसर संस्थान का संचालन किया जा रहा है।
- ख) जम्मू और कश्मीर में 11476 रोगियों को नशामुक्ति का उपचार प्रदान किया गया। 2023-24 के दौरान, स्क्रीनिंग डेटा के संबंध में गैर संचारी रोग (एनसीडी) अर्थात उच्च रक्तचाप, मधुमेह मेलेटस, मुंह का कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर और स्तन कैंसर के लिए आंकड़े 3,98,326 तक पहुंच गया है। 80,129 रोगियों की पहचान की गयी है और 80,100 रोगियों का इलाज चल रहा है।
- ग) अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के भाग के रूप में ई-सहज को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ई-सहज को रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएसएस) के साथ एकीकृत किया गया है। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) और टेली-आईसीयू विकसित किए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में सबसे अधिक कॉल प्राप्त करके संघ राज्य क्षेत्रों में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है।
- घ) संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए देश में टेली-मानस के लिए अपनी तरह के पहले चैटबॉट की भी परिकल्पना की है। विशेषज्ञ और तकनीशियनों की सेवाओं के इष्टतम उपयोग के लिए प्रभावी तरीके से रोगी प्रबंधन के लिए ई-संजीवनी, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस), स्कैन एंड शेयर, टेली मानस आदि जैसे ऑनलाइन उपायों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 1427.61 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

## 22.2 शिक्षा क्षेत्र:

- क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मॉडल स्कूल विकसित करने के लिए नए सेंट्रल सेक्टर स्कीम पीएम- स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (एसएचआरआई) का कार्यान्वयन शुरू किया है। प्रथम चरण में 233 स्कूलों के उन्नयन की मंजूरी दी गयी है। "आओ स्कूल चलें" अभियान के तहत सभी जिलों में नामांकन अभियान चलाया गया और 46,000 स्कूल न जाने वाले बच्चों का नामांकन किया गया और उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के अंतर्गत 100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले 03 आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं।
- ख) चालू वर्ष के दौरान 400 स्मार्ट कक्षाएं शुरू की गईं और 397 अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया। प्रारंभिक कक्षाओं की सभी छात्राओं और प्रारंभिक कक्षाओं के एससी/एसटी/पीएचसी श्रेणी के लड़कों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की गई। सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। 172 आईसीटी लैब और 213 व्यावसायिक लैब निर्माणाधीन हैं। चालू वर्ष के दौरान 02 जनजातीय आवासीय विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। रोबोटिक लैब वाले 100 विज्ञान नवाचार केंद्रों को भी मंजूरी दी गई है। योग प्रशिक्षण के लिए 800 स्कूलों को चिन्हित किया गया।
- ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को यूटी के सभी स्कूलों और कॉलेजों में पूरी तरह से लागू किया गया है। यूटी के 100% सरकारी कॉलेजों ने ई-समर्थ पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कराया है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के माध्यम से छात्रों का केंद्रीकृत प्रवेश शुरू किया गया, जिसमें 39954 छात्रों को इस पोर्टल के माध्यम से प्रवेश मिला। 66 सरकारी डिग्री कॉलेजों को NAAC मान्यता प्राप्त हो चुकी है।
- घ) "कॉलेज ऑन व्हील्स" पहल को 19 नवंबर, 2023 को कटरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसमें विभिन्न शीर्ष संस्थानों के 100 संकाय सदस्यों के साथ 700 छात्रों ने अनुभवात्मक शिक्षा और नवोन्मेषी प्रदर्शन के लिए जम्मू और कश्मीर ज्ञानोदय एक्सप्रेस में देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की।

स्कूल और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 1300.10 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है जो कि 2023-24 के संशोधित आवंटन से 201.32 करोड़ रुपये अधिक है।

### 22.3 समाज कल्याण एवं पुनर्वास:

- क) 277 आंगनवाड़ी केंद्रों को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से सुसज्जित किया जा रहा है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को जियो-टैग किया गया है और गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अनुसूचित जाति श्रेणियों के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पहली-आठवीं) के तहत 48905 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है। महिला हेल्प लाइन सेवा 181 स्थापित की गई है और इसे यूनिवर्सल हेल्पलाइन 112 के साथ एकीकृत किया गया है।
- ख) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कश्मीरी विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कश्मीरी विस्थापितों के लिए 880 ट्रांसिट आवास का निर्माण किया गया। संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए पीएम-पैकेज के तहत 5600 से अधिक विस्थापितों को नियमित सरकारी रोजगार प्रदान किया है। सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत कश्मीरी/जम्मू प्रवासियों के लिए नकद सहायता और खाद्यान्न सहायता को जारी रखा जा रहा है।
- ग) संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर के लिए अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है।
- घ) ऊपरी इलाकों/ऊंचाई वाले चरागाहों से पशुधन के साथ-साथ खानाबदोश परिवारों के सुचारू प्रवास के लिए मुफ्त ट्रांसह्यूमन सुविधाएं प्रदान करने के लिए यूटी के विभिन्न जिलों को ट्रक/लॉरी प्रदान की गई हैं। प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत स्मार्ट स्कूल/मौसमी केंद्र, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां और आजीविका सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में जनजातीय समुदाय के लिए छात्रवृत्ति में कई गुना वृद्धि हुई। पात्र 1.90 लाख आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए वित्तीय परिव्यय 60% बढ़ाकर 52 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- ड.) जनजातीय उत्पादों में मूल्य वृद्धि के तरीकों का पता लगाने के लिए मूल्य संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 एसटी और गुज्जर/ बकरवाल छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। प्रवासी आबादी के लिए 07 ट्रांजिट आवास स्थापित किए जा रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान 07 दुग्ध ग्राम स्थापित किये जा रहे हैं। 158 स्मार्ट स्कूलों को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है।

सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 306.82 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है। कश्मीर विस्थापितों के राहत और पुनर्वास के लिए 2024-25 के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय के तहत 1067.61 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2023-24 के संशोधित आवंटन से 134.68 करोड़ रुपये अधिक है।

## 22.4 संस्कृति:

- क) नरस्तान स्मारक, हरि पर्वत किला, जनरल जोरावर सिंह पैलेस, मुबारक मंडी और एसपीएस संग्रहालय सहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत वाले भवनों के जीर्णोद्धार के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बांदीपोरा, शोपियां, अनंतनाग, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, जम्मू और पुंछ में संस्कृति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्र में 131 पुस्तकालयों को चरणबद्ध तरीके से ई-पुस्तकालयों में बदला जा रहा है। मार्च 2024 तक 22 लाइब्रेरी पूरी तरह से ई-लाइब्रेरी में तब्दील हो जाएंगी।
- ख) जम्मू में अभिनव थिएटर और श्रीनगर में टैगोर हॉल का आधुनिक तर्ज पर नवीनीकरण और उन्नयन किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र में चार कला रूपों में अर्थात्. पेंटिंग, कविता, निबंध लेखन और गायन में सुविचरित प्रतिभा खोज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। टैलेंट हंट कार्यक्रम पंचायत से लेकर यूटी स्तर तक आयोजित किए जा रहे हैं। पुराने सचिवालय, श्रीनगर में नए "कला संग्रहालय" का चरण-। पूरा हो गया है। इस कार्यक्रम का चरण-॥ के मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है।

संस्कृति क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 111.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि 2023-24 के संशोधित आवंटन से 51 करोड़ अधिक है।

## 22.5 कौशल विकास एवं रोजगार:

- क) 2023-24 के दौरान जम्मू और कश्मीर ग्रामीण जीवनयापन मिशन (जेकेआरएलएम) के तहत 1848 महिला सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। जिला कौशल समितियों द्वारा तैयार किए गए 8 आकांक्षी/सीमावर्ती जिलों के परियोजना प्रस्तावों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) योजना के तहत अनुमोदन के लिए संसाधित किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेक्निक की ग्रेडिंग के लिए ग्रेडिंग तंत्र विकसित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक से कौशल ऋण प्रदान किया जा रहा है।
- ख) 24 आईटीआई को स्किल इंडिया पोर्टल (पीएमकेवीवाई 3.0) पर नोडल स्किल हब के रूप में पंजीकृत किया गया था। इनमें 683 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री

कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के पायलट चरण के तहत 38 सरकारी आईटीआई द्वारा 1775 अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है। इनमें से 1383 अभ्यर्थियों ने इन संस्थानों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। स्कूल छोड़ने वाले और स्कूल से बाहर रहने वाले अभ्यर्थियों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल केंद्रों को चिन्हित किया जाता है।

- ग) दिसंबर, 2023 के अंत तक 81 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं जिनमें 1259 प्लेसमेंट हुए हैं। स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत 41,382 इकाईयाँ स्थापित की गयी हैं, जिससे 1,61,449 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध हुआ है। छह जिला रोजगार और परामर्श केंद्रों (डीईएंडसीसी) को मॉडल कैरियर सेंटर (एमसीसी) के रूप में उन्नत किया गया है। अतिरिक्त 11 डीई एंड सीसी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एमसीसी के रूप में अनुमोदित किया गया है।

**कौशल विकास और रोजगार के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 165.50 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है जो कि 2023-24 के संशोधित आवंटन से 82.53 करोड़ अधिक है।**

## 22.6 खेल:

- क) वुशू खेल के लिए पुंछ, बिलावर, कुलगाम और बख्शी स्टेडियम में उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए। एमए स्टेडियम में योग केंद्र स्थापित किया गया है और यह कार्यशील हो गया है। बख्शी स्टेडियम में योग केंद्र विकसित किया जा रहा है। हैंडबॉल, आर्म रेसलिंग, जूनियर नेशनल टेनिस बॉल, क्रिकेट में राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी और जम्मू में थांग-टा लेजेंड्स लीग क्रिकेट का भी आयोजन किया गया।
- ख) जम्मू और कश्मीर ने 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2023 में फुटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो और तलवारबाजी के क्षेत्र में 04 राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की मेजबानी की। खेल में सीखने की प्रक्रिया का संस्थानीकरण करने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और वुशू अकादमियां स्थापित की गई हैं। इसके अलावा, हॉकी, जिम्नास्टिक, जल खेल, जूडो और टेबल टेनिस विषयों में खेल अकादमियाँ भी स्थापित की गई हैं।
- ग) वुशू, कयाकिंग और कैनोइंग और फुटबॉल की श्रेणी में राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए गए हैं। खेल संघों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में हैंडबॉल, डेफ क्रिकेट, डेफ शतरंज, पेनकक सिल्ट, रोइंग, सॉफ्टबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, टेनी-कोइट, थांग-ता, कुश्ती वुशू, योगासन, वॉटर स्कीइंग और जिमनास्टिक की श्रेणी में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जा

रहे हैं। श्री राकेश कुमार, सुश्री सरिता और सुश्री शीतल देवी ने दिनांक 17 से 23 जुलाई 2023 तक चेक गणराज्य में आयोजित 14वीं विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लिया और 01 स्वर्ण और 01 रजत पदक हासिल किया।

घ) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू-कश्मीर ने 6 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रीय स्तर पर, संघ राज्य क्षेत्र ने इस वर्ष दिसंबर 2023 तक 56 स्वर्ण, 47 रजत और 49 कांस्य पदक जीते। संघ राज्य क्षेत्र देश की शीतकालीन खेल राजधानी के रूप में उभर रहा है। जम्मू-कश्मीर में आयोजित शीतकालीन खेल 2023 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया।

**वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत खेल क्षेत्र के लिए, लगभग 141.80 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 31.80 करोड़ अधिक है।**

## **22.7 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति:**

क) प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, विभाग ने खाद्य आपूर्ति की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में अपने संभारतंत्र और दक्षता को बढ़ाया है। पूरे संघ राज्य क्षेत्र में सभी लाभार्थियों को प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से अपना राशन प्राप्त हुआ। विभाग ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की ट्रेकिंग पर ध्यान केंद्रित किया है और अब तक 95% उपलब्धि दर्ज की गई है। दुकानों के इस डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न भंडार की आवश्यकता को कम कर दिया है।

**वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत खाद्य और नागरिक आपूर्ति क्षेत्र के लिए, लगभग 313 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।**

## **23 अवसंरचना क्षेत्र**

### **23.1 विद्युत क्षेत्र में विकास:**

- क) चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत हानि में कमी और राजस्व सृजन में वृद्धि का सुधार देखा गया है। पुनोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) कार्य योजना में निर्धारित कार्यनिष्पादन के लक्ष्यों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। आरडीएसएस योजना के तहत विभाग का लक्ष्य जम्मू संभाग में 7.6 लाख और कश्मीर संभाग में 6.47 लाख मीटर लगाने का है।
- ख) 33 केवी बांड़ीपोरा-गुरेज़ लाइन और गुरेज़/तुलैल में 11 केवी ट्रंक लाइनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गुरेज़ को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए, आवश्यक 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के

साथ 40 एमवीए क्षमता का एक नया ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) निर्माणाधीन है। सर्दियों के दौरान सोनमर्ग को 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए जेड-मोहर सुरंग के माध्यम से भूमिगत केबल बिछाने की प्रक्रिया चल रही है।

- ग) श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए नुनवान में भूमिगत केबल बिछाने का काम शुरू, गतिशील और कार्यशील किया गया। 220/132 केवी स्तर पर, मौजूदा जीएसएस डेलिना में 160 एमवीए की क्षमता वृद्धि पहले ही हासिल की जा चुकी है; जबकि मार्च 2024 तक नए गैस इंसोलेटेड ग्रिड सब स्टेशन तेलबल, हरवान में 160 एमवीए हासिल करने की संभावना है।
- घ) 132/33 केवी स्तर पर, 150 एमवीए की क्षमता वृद्धि के साथ टेंगोरा, श्रीनगर में एक नए जीआईएस का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार, मौजूदा जीएसएस बडगाम में 50 एमवीए क्षमता वृद्धि हासिल की गई है। केन्द्रीय वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मौजूदा जीएसएस के 132/33 स्तर पर 276 एमवीए क्षमता वृद्धि की उम्मीद है।

**विद्युत क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत 1875 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 552.61 करोड़ अधिक है।**

### **23.2 जल शक्ति:**

- क) ग्रामीण घरों में 100% सार्वभौमिक जल कवरेज सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत सभी ग्रामीण घरों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। पानी के टैंकरों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) आधारित टैंकर सेवा के स्थान पर 100 प्रतिशत जीपीएस सिस्टम लगाया गया है।
- ख) उपभोक्ता रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली अब श्रीनगर और जम्मू शहरों में चालू हो गई है। उपभोक्ताओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र बैंकों की एम-पे सेवा के माध्यम से अपने बिलों का भुगतान करने का विकल्प मुहैया कराया गया है। सभी उपभोक्ताओं तक इस ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है।
- ग) झेलम नदी का बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (चरण-1) पूरा हो गया है और संगम पर झेलम की वहन क्षमता 31800 क्यूसेक से बढ़कर 41000 क्यूसेक हो गई है। व्यापक बाढ़ प्रबंधन पर यह कार्य, बाढ़ के चरणों में, झेलम नदी की वहन क्षमता को और बढ़ाएगा। वर्ष 2023-24 तक 16 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप 6500 हेक्टेयर क्षेत्र की सुरक्षा होगी।

**वर्ष 2024-25 के लिए जल शक्ति विभाग हेतु पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 5038.74 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।**



### 23.3 आवास एवं शहरी विकास:

- क) भारत सरकार ने अमृत 2.0 के तहत, संघ राज्य क्षेत्र के 78 यूएलबी (अर्बन लोकल बॉडीज) के लिए 153 परियोजनाओं हेतु संघ राज्य क्षेत्र जल कार्य योजना (यूटीडब्ल्यूएपी) को अनुमोदित किया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख नए नल से घरेलू जल आपूर्ति कनेक्शन प्रदान करने वाली 99 परियोजनाएं शामिल हैं। देविका परियोजना के तहत, 03 एसटीपी पूरे हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं और ट्रायल रन पर हैं। इसके अलावा, घरेलू कनेक्शन और सड़क नेटवर्क का काम भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। 65.33 एमएलडी की एसटीपी क्षमता वाली नई परियोजनाएं अर्थात् सांबा के लिए सीवरेज योजना (3.50 एमएलडी), अनंतनाग टाउन ज़ोन 2 और 3 में झेलम नदी का प्रदूषण निवारण (21.03 एमएलडी), डल-झील के प्रदूषण निवारण के लिए सीवरेज योजना, श्रीनगर में डल-झील के आसपास के कवर्ड क्षेत्रों के लिए एसटीपी का निर्माण (30.00) एमएलडी, बागी महताब से चदूरा (6.0 एमएलडी) तक दूध गंगा नाले में शुष्क मौसम प्रवाह के निर्वहन के लिए एसटीपी और दूध गंगा (4.80 एमएलडी) में शुष्क मौसम प्रवाह के निर्वहन के लिए एसटीपी का कार्य चल रहा है।
- ख) 6.11 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जल निकायों के कायाकल्प के लिए 23 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 12 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 47060 लाभार्थियों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 42429 आवासीय इकाइयां शुरू हो चुकी हैं और 20256 पूरी हो चुकी हैं। सम्बंधित विभाग श्रीनगर, जम्मू और अन्य प्रमुख शहरों में "महिला हाट" और महिला विशिष्ट बाजारों की स्थापना के लिए संभावित स्थलों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।
- ग) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, 262 परियोजनाओं में से, 4494 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 207 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 2721 करोड़ रु. की स्वीकृत लागत वाली 55 परियोजनाओं का निष्पादन कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र, रोप-वे परियोजना, सभागार, विद्युत सब-स्टेशन, गर्ल्स हॉस्टल, पैदल मार्ग/फुटपाथ, साइकिल ट्रेक और पार्किंग स्थानों के निर्माण के लिए कई नवीन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। स्मार्ट सिटी फंडिंग ने हरित स्थलों के विकास, एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना, वैंडिंग मशीनों की स्थापना, स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराने, पोलो व्यू मार्केट और अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट गोले मार्केट क्षेत्र जैसी प्रतिष्ठित सड़कों के विकास को भी बढ़ावा दिया है।
- घ) दोनों राजधानी शहरों के लिए व्यापक मोबिलिटी योजनाएँ तैयार की गई हैं। सम्बंधित विभाग जम्मू और श्रीनगर शहरों के नागरिकों के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और अंतिम छोर तक पहुँच सुविधा (लास्ट माइल कनेक्टिविटी)के लिए ई-वाहनों की शुरूआत को बढ़ावा दे रहा है। इस प्रयास में, सार्वजनिक परिवहन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ नेटवर्क को सुनिश्चित करने के लिए 200 ई-बसें शुरू करना, सार्वजनिक साइकिल साझा करना और ई-

साइकिल तथा ई-3 व्हीलर (ई-ऑटो) प्रदान करना जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

**वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत, आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए लगभग 2329.55 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।**

#### **23.4 सड़कें तथा पुल:**

- क) विभाग पिछले चार वर्षों से प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्र और केंद्रीय योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान कुल मिलाकर 4500 किमी सड़कों की ब्लैक-टॉपिंग हासिल होने की उम्मीद है।
- ख) नाबार्ड के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 में 1292 करोड़ की फंडिंग के साथ 276 नई परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए नाबार्ड फंडिंग के तहत वर्ष 2023-24 में 821 करोड़ रुपये की लागत से 183 सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इन्हें शुरू किया गया।
- ग) 20 वर्ष पूरे कर चुके पुलों का सुरक्षा ऑडिट वर्ष 2022-23 के दौरान पूरा किया गया है। 10 साल पूरे कर चुके पुलों का सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया गया है। 60 स्वीकृत पुलों को वर्ष 2023-24 के दौरान पूरा किया जाएगा।

**वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत, सड़क और पुल क्षेत्र के लिए, लगभग 4108.87 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 166 करोड़ अधिक है।**

#### **23.5 उद्योग और वाणिज्य:**

- क) विकास के लिए 46 नए औद्योगिक क्षेत्रों (आईई) की पहचान की गई है। इनमें से, 15 औद्योगिक क्षेत्र की परियोजनाएं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) और भारतीय रेलवे निर्माण लिमिटेड (इरकॉन) को सौंपी गई हैं। लघु उद्योग विकास निगम (सिडको) और लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड (सिकोप) के माध्यम से 04 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा, सिडबी के माध्यम से वित्त-पोषण के लिए 06 परियोजनाओं की पहचान की गई है और 13 परियोजनाएं सीपीडब्ल्यूडी को सौंपे जाने की प्रक्रिया में हैं।
- ख) औद्योगिक क्षेत्र (आईई) सेमपोरा, आईई राख गुंड अक्सा, बेमिना और आईई लेलहार पुलवामा को मेडिसिटी घोषित किया गया है। कश्मीर संभाग के मेडिसिटीज में भूमि आवंटन के लिए इच्छुक उद्यमियों/आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर

- रोजगार सृजन कार्यक्रम (जेकेआरईजीपी) के तहत 29 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सहित 1088 इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिनकी रोजगार क्षमता 6528 है।
- ग) व्यापार संवर्धन संगठन (टीपीओ) ने जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में विभिन्न ई-कॉमर्स ऑन-बोर्डिंग ड्राइव जैसे जीईएम ऑन-बोर्डिंग, ओएनडीसी, फ्लिपकार्ट आदि का आयोजन किया है। जेएंडके टीपीओ ने प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ 14 जीईएम ऑन-बोर्डिंग ड्राइव और 08 ऑन-बोर्डिंग ड्राइव का आयोजन किया है। जेएंडके टीपीओ का लक्ष्य विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर 300 से अधिक एमएसएमई को शामिल करना है। समाधान 2.0 लागू किया जा रहा है। यह पोर्टल, विलंबित भुगतान के लिए याचिकाकर्ताओं को एक इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
- घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 24 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई हैं। टीपीओ ने 07 प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया है/ उनमें भाग लिया है। 109 उद्यमिता विकास/अभिमुखता/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। 105 नए स्टार्ट-अप पंजीकृत हुए और 7 स्टार्टअप को निधियाँ जुटाने में सहायता दी गई। बसोहली पेंटिंग, बसोहली पशमीना और राजौरी चिकरीवुड को वर्ष 2023-24 के दौरान जीआई टैग दिया गया है।

**उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 529.62 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 133.35 करोड़ रुपए अधिक है।**

### **23.6 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:**

- क) पीएम कुसुम स्कीम के तहत 827 सोलर कृषि पंप लगाए गए हैं। जम्मू में 5771 किलोवाट की संचयी क्षमता के साथ 955 घरों में सौर ऊर्जा की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस परियोजना के तहत 5593 किलोवाट की संचयी क्षमता के साथ 1102 घरों में सौर ऊर्जा उपलब्ध करायी गई है। विभाग, नवीन परियोजना की रूपरेखा तैयार करके सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू कर रहा है।
- ख) चन्नी हिम्मत, जम्मू में ऊर्जा भवन के निर्माण की मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार परिषद ने लाल मंडी, श्रीनगर में नवाचार प्रसार केंद्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू की है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, जम्मू की स्थापना के लिए चोवादी, जम्मू में साइट की पहचान की गई है।

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 159.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से 71.50 करोड़ रुपए अधिक है।**

### 23.7 परिवहन:

- क) मोटर वाहन स्क्रेपिंग नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम-2023 को अधिसूचित कर दिया गया है और ओला, उबर, आला कैब, नोवा आदि को एग्रीगेटर लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। उनकी सेवाएं जम्मू और श्रीनगर शहरों में भी शुरू कर दी गई हैं। महिला चालकों के साथ एग्रीगेटर्स मोटर वाहन चलाने वाले के लिए प्रोत्साहन रखा गया है।
- ख) जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम द्वारा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) शुरू किया गया है और प्रमुख मार्गों पर ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा उपलब्ध है। विभाग, साझेदारी मोड में स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण सुविधा शुरू करने पर कार्य कर रहा है।

**परिवहन क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 22 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 8.11 करोड़ रुपए अधिक है।**

### 24 आंतरिक सुरक्षा

- क) केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में घुसपैठ रोधी ग्रिड को सुदृढ़ बनाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में 42 नई सीमा पुलिस चौकियों (बीपीपी) के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। 21 स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और 30% निर्माण कार्यों को 119.83 लाख के व्यय के साथ पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा, प्रमुख टावरों/जैमरों के निर्माण और स्थापना के लिए 14 जेलों की पहचान की गई है।
- ख) 20.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इंद्रा नगर, श्रीनगर में पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए होस्टल के निर्माण और असरवां, भलवाल जम्मू में पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए होस्टल के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) श्रीनगर में नारकोटिक्स प्रयोगशाला और एफएसएल, जम्मू में टॉक्सिकोलॉजी और नारकोटिक्स प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है। एफएसएल, श्रीनगर में भौतिकी और बैलिस्टिक प्रभाग की स्थापना की जा रही है। पुलिस थानों और पुलिस चौकियों के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का कार्य कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।
- ग) संघ राज्य क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर के 17 जिलों के चिन्हित स्थलों पर जीआईएस-आधारित सीसीटीवी कैमरों के एकीकृत नेटवर्क पर कार्य चल रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन से राष्ट्र-विरोधी तत्वों और अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद मिलेगी, किसी भी घटना या कृत्य पर पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी और कानून प्रवर्तन और अन्य बाहरी एजेंसियों के साथ सुगम और प्रभावी संचार होगा।

**सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए राजस्व और पूंजीगत व्यय के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 1284.45 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।**

**25. चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान:**

- क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल अनुदान 1,18,500 करोड़ रुपये था। वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान 1,08,197 करोड़ रुपये का है, जिसमें अर्थोपाय संबंधी अग्रिम प्रावधान शामिल नहीं हैं। अपेक्षित राजस्व प्राप्तियाँ 84,603 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियाँ 23,594 करोड़ रुपये हैं। इसी प्रकार, राजस्व व्यय 76,155 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 32,042 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक, मांग संख्या 06 - विद्युत विभाग, 08 - वित्त विभाग, 24-आतिथ्य और प्रोटोकॉल और 36 - सहकारिता विभाग के संबंध में इस अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं और उद्देश्यों पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से अनुदान के अलावा 8,712.8972 करोड़ रुपये की राशि निकाली जाएगी। ऐसा मुख्यतः बिजली खरीद (विद्युत विभाग), पेंशन, ब्याज भुगतान, ऋण की अदायगी (वित्त विभाग), द्वारका, नई दिल्ली में भूमि खरीद (आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग) और सहकारिता विभाग में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) में सहायता की नई योजना से संबंधित व्यय के कारण यह आवश्यक हो गया था।
- ग) तदनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की समेकित निधि से 8,712.8972 करोड़ रुपये के भुगतान और समायोजन को अधिकृत करने के लिए पूरक जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक संख्या (01) प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

**26 संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए लेखानुदान 2024-25:**

- क) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट अनुमान 1,18,728 करोड़ रुपये है, जिसमें अर्थोपाय संबंधी अग्रिम का प्रावधान शामिल नहीं है। अपेक्षित राजस्व प्राप्तियाँ 97,861 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियाँ 20,867 करोड़ रुपये हैं। इसी प्रकार, राजस्व व्यय 80,162 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और पूंजीगत व्यय 38,566 करोड़ रुपये होने की संभावना है।
- ख) वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित "लेखानुदान" के संबंध में कुल प्राप्तियाँ 59,364 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिसमें 16,568 करोड़ रुपये के अर्थोपाय संबंधी अग्रिमों का प्रावधान शामिल नहीं है। वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित "लेखानुदान" के संबंध में इन प्राप्तियों में

48,930 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियों के रूप में और 10,434 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में शामिल हैं। कर और गैर-कर दोनों का राजस्व 15,158 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर को 18,639 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में और सीएसएस/पीएमडीपी के रूप में 8424 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

- ग) वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित "लेखानुदान" के संबंध में कुल सकल प्राप्तियां 75,932 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जिसमें 16,568 करोड़ रुपये के अर्थोपाय संबंधी अग्रिमों का प्रावधान भी शामिल है। इन प्राप्तियों के मद्देनज़र कुल सकल व्यय 75,932 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अर्थोपाय अग्रिमों के प्रावधान को छोड़कर, कुल निवल व्यय 59,364 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 19,283 करोड़ रुपये का अनुमानित पूंजीगत व्यय और 40,081 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व व्यय शामिल है।
- घ) तदनुसार, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की समेकित निधि से 75931.9699 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए "लेखानुदान" संबंधी जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक संख्या (02) प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

## 27 राजकोषीय संकेतक:

- (क) वर्ष 2024-25 के लिए कर/जीडीपी अनुपात 7.84 प्रतिशत अनुमानित है जो पिछले वर्ष के 6.56% की तुलना में अधिक है।
- (ख) वर्ष 2024-25 के लिए ऋण/जीडीपी अनुपात 51% है।
- (ग) वर्ष 2024-25 के लिए 2,63,399 करोड़ रुपए के जीडीपी का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्शाता है।

28 अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के अनुपूरक बजट (01.04.2023 से 31.03.2024 के लिए), और "लेखानुदान" 2024-25 को आगे विचार हेतु सदन में प्रस्तुत करती हूं।

\*\*\*\*\*

**Supplementary Demands for Grants 2023-24 and  
Interim Budget 2024-25  
of  
the Union Territory of Jammu and Kashmir (with Legislature)**

**Speech of  
Nirmala Sitharaman  
*Minister of Finance***

**Mr. Speaker Sir,**

1. The Union Territory (UT) of Jammu and Kashmir is marching rapidly ahead on the path of socio-economic development since the transformative reforms of August 2019. The Union Territory Government is committed to pursue the path of accelerated and inclusive growth which enables its citizens to shape their destiny and discover new aspirations. The long-term vision of the Union Territory Government stresses on strengthening good governance and grass-root democracy, promoting sustainable agriculture and industrial development, nurturing employment generation and responsible tourism, and ensuring women empowerment and social inclusion.
2. The crucial reforms undertaken in 2019 enabled path-breaking measures by the Union Territory Government to decentralize governance structure, promote inclusive development, improve efficiency and transparency of public expenditure, upscale revenue generation, minimize wasteful expenditure, and step up infrastructure development.
3. The Government is maintaining law and order to ensure security while simultaneously implementing initiatives for economic and social development. The Government has adopted a policy of zero tolerance against terrorism. Security forces are taking effective and continuous action in countering terrorism. Due to the effective measures and efforts taken, the security scenario in Jammu and Kashmir has significantly improved.

#### 4. **Decentralizing Governance**

- a. For strengthening people's voice and decentralizing governance in rural areas, the 73<sup>rd</sup> Amendment to the Constitution was adopted and the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 was amended in 2020. The Panchayati Raj Institutions (PRIs) were consolidated by providing three crucial 'F's - funds, functions and functionaries. Twenty-seven subjects were transferred to these institutions for ensuring properly defined role for these institutions in local planning, decision making and supervision.
- b. The elections to the first PRI tier were held in November, 2018 and to the second tier of Block Development Councils (BDCs) in November-December, 2019. The District Development Councils (DDCs) were constituted for establishing a functional Panchayati Raj system as mandated under the 73<sup>rd</sup> Constitutional Amendment. For the first time in the history of Jammu & Kashmir, direct elections were conducted in 280 DDC constituencies. 3991 Sarpanches & 28521 Panches, 264 BDC Chairpersons and 280 DDC members were elected.
- c. Grants to the tune of Rs. 1642.06 crore under the fourteenth Finance Commission were held up from 2016-17 for non-conduct of Panchayat elections. These funds were unlocked and released in 2019-20 to the Halqa Panchayats through PFMS system. The Gram Panchayat Development Plans (GPDPs) were framed through participatory planning. These GPDPs are being regularly uploaded on e-Gram Swaraj Portal.
- d. Massive Capacity building exercise were carried out for all PRIs and about 6,000 elected representatives were sent on exposure cum training visits to learn best practices of other States/ UTs. Power to grant building permissions in rural areas was delegated to PRIs at panchayat level. Monthly honorarium is being provided for the elected representatives of the PRIs of all the three tiers.



## 5. **Strengthening Public Outreach**

- a. After the re-organization, Jammu and Kashmir has embarked on the ambitious Back to Village (B2V) programme for reaching out to the people at the grass-roots and understanding their felt needs. Till now, five rounds of this programme have been conducted from 2018-19 to 2023-24. The Administrative Secretaries, Heads of Departments, Gazetted Officers, and other Government Officers have regularly toured to all 4291 panchayats and held detailed interactions at respective panchayats to redress the grievances of common people. Prabhari Officers were appointed in all panchayats for conducting monthly meetings with all the line departments for redressal of the grievances and follow up of issues related to local development.
- b. As a sequel to B2V programme, the unique initiative of “Aspirational Block Development” programme was started for upliftment of backward blocks. The blocks were judiciously chosen and Rs. 44 crore (Rs.1 crore per block) was provided for accelerated development of such blocks. “Aspirational Panchayat Development” programme for providing financial assistance to selected 285 panchayats (one panchayat per Block) was also launched for their holistic development.

## 6. **Legal Reforms for Social Justice**

- a. Prior to the Constitutional reforms of 2019, the people of Jammu and Kashmir were deprived of benefits of important central legislations, like the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1954, the Whistle Blowers Protection Act, 2014, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and other important central legislations. After the 2019 reforms, all the provisions of the Constitution and all Central Acts have been made applicable to the UT.

- b. Prior to August, 2019, several sections of the society, like West Pakistani Refugees, Safai-Karamcharis and Valmikis who were residing in Jammu and Kashmir since independence, were not entitled to vote in the assembly and PRI elections. The reforms enabled extension of such basic democratic rights to these sections. Further, important segments of society like, the West Pakistani Refugees, Safai-Karamcharis and Valmikis, children of local women married outside Jammu and Kashmir and other similarly situated persons had remained deprived of their basic rights. The reforms of 2019 helped such residents of Jammu and Kashmir get domicile certificates and become eligible for applying to government jobs and such other similar benefits.
- c. Jammu and Kashmir Reservation Act, 2004 has been amended to extend the reservation to the persons residing in the areas adjoining actual line of control and adjoining International Border in direct recruitment, promotions and admissions in different professional courses. The percentage of reservation was increased from 3% to 4% for such persons.
- d. As part of affirmative action, reservation has been extended to Pahari Speaking People and the economically weaker sections of the society for their upliftment. Recently, the Parliament has amended the Jammu and Kashmir Reservation Act to bring “Other Backward Castes” of Jammu and Kashmir at par with other parts of the country. Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 was recently amended to provide representation in the Legislative Assembly of UT by way of nomination to Kashmiri migrants and displaced persons from areas of Jammu and Kashmir under occupation of Pakistan.
- e. Earlier, no political reservation, i.e. reservation of seats in the Legislative Assembly of UT, was available to the persons belonging to Scheduled Tribes (ST). With the Constitutional changes and enactment of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019, seats have been reserved in Legislative Assembly for persons belonging to ST community.

## 7. **e-Governance initiatives**

- a. Ushering in a new era of digital governance, the Union Territory Government transitioned from physical files to the electronic system of e-Office. Over 450 government offices upto district level have adopted the e-Office. This adoption enabled the Government to end the 150 year-old darbar move and save about Rs. 400 crore annually.
- b. This drive for information technology in governance has ensured that several key services of various departments are provided online. It eliminated the need to approach government offices for routine services and benefits. Jammu and Kashmir achieved a remarkable feat by offering over 1100 citizen centric services online and thus securing the top spot nationwide and setting up new benchmark in digital governance.
- c. Jammu and Kashmir was ranked first amongst Union Territories in National e-Service Delivery Assessment in 2021 in both the state portal and services categories. Robust citizen feedback mechanism has been created and online services were opened for feedback. Jammu and Kashmir is leading among the Union Territory with maximum number of services linked with Rapid Assessment System (RAS).
- d. Public Services Guarantee Act (PSGA) was amended to encompass online services for ensuring time-bound delivery. The Mobile-Dost app and Digi-Dost initiatives further extend mobile governance and door-step delivery of services; thereby promoting digital inclusion. Jammu & Kashmir Integrated Grievance Redressal & Monitoring System (JK-IGRAMS) was created to facilitate citizens to lodge a grievance online. The portal also enables the citizens to track the grievance online.
- e. This digital revolution in the Union Territory signifies a paradigm shift towards enhancing transparency, accountability, and efficiency in governance across all levels.

## **8. Improving Transparency and Efficiency in Governance**

- a. To further enhance transparency in land administration, the Aapki Zameen Aapki Nigrani portal was created. This allowed the citizens to access their land records online. 29 lakh land holders in the Union Territory today have a land passbook containing details of all parcels of land under their ownership. Registration of land revenue documents has been made online. Registrations are completed within a day. 2,53,083 registrations have been made since 2019 and Rs. 1505.70 crore revenue has been realized.
  
- b. Details of all developmental works were made available online on the EMPOWERMENT / JANBAGHIDARI portal. The portal enables citizens to view all ongoing works online without any restrictions. Public monitoring of works in online mode has led to reduction in construction cost and fast-tracking of work execution. The Union Territory government ensured accountability in development by starting physical verification of works through the field officials of Planning Department. The online PROOF (photographic record of on-site facility) platform was introduced to track work progress with geo-tagged photographs at pre-and post-execution stages.
  
- c. General Financial Rules were introduced in the Union Territory to nurture discipline in approval, bidding, and execution processes. The Union Territory government started IT reforms to streamline financial management by ensuring work-wise allocation of funds through BEAMS (Budget, Estimation, Allocation & Monitoring System) platform. Further procurement of goods and services through Government e-Market Place (GEM) was universalized to enable competitive purchases and cost savings. The Union Territory Government received the Gold medal for its major progress in GEM based procurement.

## **9. Accelerating Infrastructure Development**

- a. The Union Territory Government made judicious capital investments to accelerate infrastructure development. As several projects were remained stalled in 2018-19, the Union Territory Government

prioritized such languishing projects based on their economic potential and social importance. For the prioritized projects, the Government provided accelerated funding and commissioned 1632 projects with cost of Rs 3218 crore.

- b. Prime Minister's Development Package has provided a major push to bridge the infrastructure deficit of the UT. Under this Package, an amount of Rs. 46,981 crore was released for 53 projects. An amount of Rs. 45,448 crore has been utilized till December, 2023 and 33 projects have been completed.
  
- c. **Power Sector-** To harness its hydro-electric potential, the Union Territory Government partnered with NHPC to develop the 624 MW Kiru, 850 MW Ratle, 1000 MW Pakal Dul and 540 MW Kwar projects. Till date Government of India has provided Rs.1300 crore for equity contribution to Union Territory for Kiru, Kwar and Ratle projects. By expanding the installed hydro power capacity from 3500 MW to about 6500 MW, the government aims to harness the natural advantage and lower its power purchase cost. The work on these projects is going on in full swing. MoU was also signed with NHPC for development of further 04 hydro power projects, namely Sawalkote (1856 MW), Dul Hasti stage-II (258 MW), Uri-I stage -II (240 MW), and Kirthai-II (930 MW), with total capacity of 3284 MW. Investment of about Rs. 50,000 crore will flow in Jammu and Kashmir through these projects. The UT will also benefit from its share of free power, long term supply of stable power, expansion of economic activities, and creation of job opportunities.
  
- d. In the Transmission sector, 1940 MVA capacity was added since 2019 at 220 KV level by way of creation/ augmentation of 8 Grid Stations. 2080 MVA was added at 132 KV level by way of creation/ augmentation of 30 Grid Stations. 467 km of new transmission lines were laid. In the Distribution sector, 1753 MVA capacity was added at 66-33 KV level by way of creation/ augmentation of 266 Sub-stations. Total 10953 km of new HT and LT lines were laid. 1255 MVA capacity

was added at 11 kV level by way of creation/ augmentation of 9071 distribution transformers.

- e. For the first time since independence, Gurez Valley in northern Kashmir has been connected to the electricity grid. This massive expansion of transmission capacity by 150% during 2019-2023 has enabled the expansion of electricity supply to interior villages and the fulfillment of much higher demand. Smart metering has been undertaken to reduce losses, improve revenues, and facilitate consumers track their consumption. 4.61 lakh smart meters have been installed by January 2024.
- f. The Union Territory Government has worked tirelessly to develop renewable sources of energy, including small hydropower projects and solar power projects. The Science and Technology department executed rooftop solar projects in Jammu and Srinagar cities.
- g. **Roads & Railways** - The railway link between Jammu to Srinagar is being constructed in full swing. Kashmir is expected to be rail-connected to rest of the country in the year 2024. World's highest rail bridge has been constructed on Chenab River.
- h. The government also expanded and strengthened road network through Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) and Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) funding. Over 7000 km of roads to various villages has been constructed under PMGSY in the past four years. Considering data of the 2001 census, all rural settlements have been connected under the Prime Minister's Gram Sadak Yojana, and work is underway to provide connectivity to the remaining villages figuring in the 2011 census data.
- i. Through close monitoring and accelerated execution, the road construction speed has doubled. While 2914 projects got completed and 9382 kms of roads were blacktopped during 2017-20, over 7820

projects were completed and 17248 km roads got blacktopped during 2020-23. This has substantially improved road connectivity to remote villages and substantially reduced traveling times in this Himalayan UT.

- j. A new milestone has been achieved by up-gradation of Jammu-Srinagar National Highway by way of constructing 8.45 km long twin tube Qazigund-Banihal tunnel at an estimated cost Rs 3017 crore. Work on 13.15 km 2-lane bi-directional Zojila tunnel with 14.20 km parallel escape on Srinagar-Leh road is in progress at an estimated cost of Rs 4509 crore.
- k. Work on 6.40 km Z-Morh tunnel on Srinagar Sonamarg road is in progress at an estimated cost of Rs 2379 crore. Project for Sudhmahadev–Dranga tunnels I & II (8 kms) on NH- 244 was approved by MoRTH on EPC mode for an amount of Rs. 3703 crore. Work on 1.574 km Khellani Bypass tunnel on NH 244 has been taken up at an estimated cost of Rs 431.28 crore and 70% physical progress has been achieved. Work on 495 m tunnel of NH 244 from Chamoti to Drabshalla is also in progress.
- l. Work on semi-ring road for Jammu (58 km) is nearing completion with 52 km length getting constructed. Work on 4-laning semi-ring road for Srinagar is moving ahead with 39% work (Phase-I) being completed. Double laning of Akhnoor-Poonch road has been taken up at a cost of Rs 3685 crore, which will hugely benefit population in Poonch and Rajouri districts.
- m. **Irrigation & Water Supply** - There has been a dramatic improvement in provision of water supply to households in the entire Union Territory. The government invested capital funds in construction of bore-wells and tube-wells, commissioning of water treatment plants, development of overhead tanks, and laying of pipe network. This helped in rapidly expanding the household tap connections from 5.70 lakh covered before 2019 to about 14.20 lakh rural households by January 2024 through funding under Jal Jeevan Mission.

- n. Tawi Barrage project, envisaging creation of an artificial lake to enhance tourism potential of Jammu, has been recommenced after 08 years. Project execution is in full swing and likely to be completed at a cost of Rs. 64.80 crore. Work on Shahpur Kandi Dam project has been undertaken in right earnest. This will pave the way for Jammu and Kashmir to get its due share of 1150 cusec water from the river Ravi and resolve a long pending issue.
- o. Flood Management program of river Jhelum and its tributaries (Phase-I) has been completed, thereby increasing the carrying capacity of Jhelum from 31800 cusec to 41000 cusec at Sangam confluence point. In the aftermath of the flooding of Jhelum river, 213 projects were undertaken with concessional assistance of 250 million USD from World Bank. Of these, 175 projects have been already completed and 38 projects are being actively executed. Project expenditure has cumulatively reached Rs. 1320 crore.
- p. **Urban Development & Housing** - Planned development of residential infrastructure in satellite cities is underway, with mass housing colonies and new townships being established in Kot Bhalwal, Chatterhama, and Gund Aksa. Efforts for smart mobility, digital governance, and sustainable development have made Jammu and Srinagar a new model of urban transformation for other cities in the UT.
- q. Under Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) programme, the affordable houses were completed at Sunjwan, Jammu and handed over to eligible beneficiaries on 2nd August, 2023. The government completed several infrastructure projects for water supply, sewerage and solid waste management in various municipal areas through AMRUT funding.
- r. Under Smart City programme, both Jammu and Srinagar cities witnessed revamp of urban infrastructure and services. By pooling the schematic funding with convergence funds and promoting public private partnerships, the government was able to mobilize private



sector finance for improving urban infrastructure. Moving towards green urban transport, the Government is plying 150 electric buses (e-Buses) in the twin capital cities, aiming at efficiencies and economies in operations and better user experience.

## 10. **Unlocking Economic Potential**

- a. **Agriculture & Allied sectors** – Recognizing the crucial importance of agriculture and allied sectors for rural livelihoods, the Union Territory Government is working towards bringing all farming land under two-crop patterns. The cold storage capacity has been augmented by 68% from 1.133 lakh MT in 2018 to 1.910 lakh MT in 2022. The UT will cross the 2 lakh MT capacity mark by March 2024. In order to ensure economic security for farmer families, a total of 14.83 lakh Kisan Credit Cards (KCC) have been distributed so far.
- b. More than 12000 hectare area is now added under high density fruit plantation. This will substantially increase the income of apple growers. The Government is also providing suitable market linkages and air transportation to identified perishable fruits and vegetables under 'PARVAZ' scheme. Total 23 mandis have been integrated with electronic National Agricultural Market (e-NAM).
- c. The Union Territory Government is investing in turning around the agriculture sector by strongly investing in quality seeds, farm mechanization, high density plantation, cold storages, and farmers insurance. Thus, the government rolled out the 29 interventions in Agriculture & allied sectors under the "Holistic Agriculture Development Programme" with the allocation of Rs. 5013 crore.
- d. This programme is expected to double the value addition from these sectors, boost the sectoral growth rate to 11%, create employment opportunities for over 2.87 lakh youth and establish around 19000 enterprises within the next five years.

- e. **Rural Development** - Jammu and Kashmir has been ranked the third in the monthly income of agriculture households and the fifth best performing State/UT in agriculture and allied sectors. The UT secured the third ranking in the country in constructing 75 Amrit Sarovars in each district. 3336 Amrit Sarovars were completed in the UT, which are providing impetus to local tourism and augmenting water resources for agricultural and domestic purposes.
  
- f. 5 marla land has been allotted to 469 landless families under Awaas Plus PMAY-G (Pradhan Mantri Awas Yojana- Grameen) beneficiaries. The number of houses getting constructed annually has quadrupled to 51290 in 2022-23 and crossed 47100 by January 2024. The number of annual works under MGNREGA also quadrupled from 54,315 in 2019-20 to over 200,000 by January 2024.
  
- g. **Tourism** - Tourism department invested in improving tourism infrastructure and services and promoting tourist attractions. The Union Territory earned global laurels when it hosted the Tourism Working Group meeting of the G20 nations from 22 to 24 May, 2023 at Srinagar. This event has served as a significant milestone in the progress and development of tourism in Jammu and Kashmir.
  
- h. To accommodate the increasing tourist flow and provide quality services, the Union Territory Government devised the homestay guidelines. More than 1485 homestays with the bed capacity of 13,000 have been registered so far. After granting industry status to the tourism sector, investment in this sector has seen enormous growth. Initiatives are being undertaken to involve local communities in tourism activities and to ensure equitable benefit sharing. These initiatives helped the tourism sector in the UT to do exceptionally well. The sector witnessed unprecedented growth with over 1.88 crore tourists visiting Jammu and Kashmir in 2022 and 2.11 crore in 2023.

## **11. Stepping up Industrial Development**

- a. The Union Territory Government launched the Jammu and Kashmir Industrial Policy 2021-30 with the aim to attract new investment, create employment opportunities for youth, develop backward regions and expand existing industrial units. In pursuance to these objectives, the Industrial Land Allotment Policy 2021-30, Private Industrial Estate Development Policy 2021-30, Wool Processing, Handicrafts and Handloom Policy 2020 have been notified.
- b. Apart from the existing 64 industrial estates, 46 estates are being developed to fulfill the goal of 'Made in Jammu and Kashmir'. Investment proposals worth Rs. 90182 crore were received which have potential to generate employment for 4,01,965 youth. Since 2019-20, an investment worth Rs.5319 crore has been grounded. The Start-up policy is also being finalized during the current financial year 2023-24. Karkhandar Scheme is being implemented to provide fresh impetus to the craft industry.
- c. Jammu and Kashmir emerged as the top ranking Union Territory of India in the 2022 Export Ranking. The Union Territory improved its ranking from 35 in 2020 to 17 in 2022. Handloom and Handicraft exports have doubled from Rs. 563 crore in 2021-22 to Rs. 1116 crore in 2022-23.

## **12. Expanding Employment Avenues**

- a. The Union Territory Government launched a massive recruitment drive after the 2019 reforms. Since August 2019, 31,830 selections have been made in fair, transparent, and expeditious manner. Interviews have been dispensed for the posts upto the pay level – 5. Further, 12,264 recruitments for various posts are in pipeline.

- b. Employment generation was also encouraged through self employment schemes and financial assistance from banks. Under the Mission Youth initiatives of Mumkin, Tejaswani, Spurring Entrepreneur programme, financial assistance is being provided to large number of youth and women entrepreneurs.
- c. In order to secure the future of workers in the unorganized sector, more than 34 lakh labourers have been registered on the e-Shram portal. Efforts are underway to extend the benefits of Prime Minister's Shram Yogi Maandhan Yojana to all workers in this sector.
- d. The Union Territory Government is working intensively to strengthen the cooperative sector. With the objective of linking Primary Agricultural Credit Societies (PACS) electronically with District Central Cooperative Banks, and bringing about transparency in credit provided to farmers and members of cooperatives, 537 PACS have been prioritized. The government is aiming to have one approved PACS in every Panchayat that operates inclusively and supports local economy.
- e. Credit Card Scheme for artisans and weavers is being implemented with an attractive interest subvention of 7%. Financial support is being provided for Cooperatives/Self Help Groups (SHGs) and Food Producer Organizations (FPOs). The number of SHGs/FPOs is being increased for credit expansion.

### 13. **Improving Quality of Life**

- a. **Health** - Jammu and Kashmir became the first in the country to launch SEHAT(Social Endeavour for Health and Telemedicine Initiative), the Universal Health Insurance scheme, to provide universal health insurance of Rs. 5 lakh per family, free of cost, to all residents of the UT. Going beyond the national norm under Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (AB-PMJAY), the coverage was extended to the entire Union Territory under SEHAT scheme. Over

83.50 lakh persons are issued the SEHAT Golden Cards. About 229 hospitals are empanelled under AB-PMJAY /SEHAT scheme for providing quality health care. About 10.70 lakh treatments have been provided so far which has reduced out of pocket expenditure of Rs. 1844 crore for patients. The Union Territory received Prime Minister's award for this initiative.

- b. The Union Territory Government has started over 3000 health and wellness centres since 2019. The Jan Aushadhi centres have been expanded from 38 in 2019 to 270 by December 2023. Over 480 new ambulances have been mobilized for emergency care. The coverage under National Health Mission and National Ayush Mission has been made comprehensive. These measures have helped the Union Territory reduce IMR from 22.0 in 2019-20 to 16.3 in 2023-24 as also improve sex ratio at birth from 927 in 2019-20 to 976 in 2023-24.
- c. There has been an unprecedented expansion in medical education with establishment of new Medical Colleges. About 4500 seats have been added in MBBS, post-graduation, and nursing education within the past four years. Seven new government medical colleges have been started and operationalized. 28 BSc nursing colleges (including private) and 19 BSc paramedic colleges have been added (including private).
- d. **Education** – The proper nutrition and education in the first 5 years of human life are often considered the most crucial investments. The Union Territory Government has embarked on the initiative to provide early childhood education by starting development of 15000 pre-primary schools. The congenial environment in the UT since 2019 has enabled rapid increase in enrollment of students in primary, middle and secondary schools with enrollment rising from 12.40 lakh in 2019-20 to over 15 lakh in 2022-23. Thrust has been provided to girls' education. The punctuality and working discipline of teaching staff was enhanced by installing facial recognition based attendance systems in all the schools.

- e. The Union Territory witnessed spurt in higher education with 51 new degree colleges getting established since 2019. The National Education Policy 2020 was operationalized and the four year undergraduate programmes have been initiated in all colleges in the UT. 66 colleges got the prestigious NAAC accreditation. To facilitate online education, electronic content for 50 subjects has been developed and uploaded. The Union Territory Government instituted the unique feedback portal to evaluate teachers and institutions. Centralized admission process based on CUET (Common University Entrance Test) score was started through e-Samarth portal. The college and university infrastructure got a major boost through projects under Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyaan (RUSA) funding. The prestigious national institutes, like IIT Jammu and IIM Jammu, were made functional by providing land and other incentives.
  
- f. **Sports** - The 2019 reforms have ushered in a sports revolution in Jammu and Kashmir. There has been a complete revitalization of sports in the UT through completion of 702 sports projects, construction of 100 Khelo India Centres and development of indoor sports complexes across the UT. Multipurpose indoor sports halls have been constructed in almost every district. Playfields have been developed in every panchayat. Floodlighting and synthetic turfing is being installed in several stadia.
  
- g. International level sports facilities are being developed in Jammu and Srinagar. Centres of Excellence have been established in Canoeing, Rowing and Fencing in both Jammu & Kashmir divisions. Synthetic Hockey Turf, KK Hakku Stadium, Jammu and Synthetic Hockey Turf, Pologround, Srinagar were constructed and approved by Federation of Indian Hockey (FIH). Synthetic football turf is being developed at Khel Gaon, Nagrota.

#### 14. **Assuring Financial Inclusion**

- a. The Union Territory Government has prioritized setting up of brick and mortar branches in the unbanked villages with population more than

3000. Out of the priority 167 villages, 162 villages have been covered through banking correspondents or brick and mortar branches. Financial literacy drives have been undertaken in coordination with the scheduled banks.

- b. Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Rs. 4348 crore loans have been disbursed to 1,84,681 beneficiaries till December 2023. Rs. 5880 crore loans were disbursed to 7.50 Lakh KCC (Crop) account holders and Rs 1296 crore to 1.72 Lakh KCC-AHF (Animal Husbandry & Fisheries) account holders. Under the PM-SVANidhi Scheme, special credit facility with a working capital upto of Rs10,000, Rs 20,000 and Rs 50,000 has been disbursed to over 23100 street vendors.
- c. The UT Government, being the promoter of the J&K Bank, strove to improve its capital adequacy and corporate governance. The Union Territory Government facilitated the reforms to limit concentration of power, professionalization of the Board and Management. When the Bank suffered losses due to Covid-19 impact and the consequent high NPAs, the Union Territory Government reinforced the Bank by infusing substantial equity capital over 2019 to 2022. These steps facilitated transformation of the Bank's financial health and enabled its business growth and transition out of losses of the pre-2019 period. The Union Territory Government also launched the Interest Subvention scheme to tackle the economic shock of the Covid pandemic. This enabled several business enterprises to sustain and protected the Banking sector.

## **15. Expanding Social Inclusion**

- a. The Union Territory Government has doubled its social security cover for widows, old aged and physically challenged persons. The monthly assistance/pensionary benefits were expanded from around 5.0 lakh beneficiaries in 2014-15 to about 8.5 lakh in 2022-23. The UT achieved saturation by extending pensionary benefits to all eligible beneficiaries registered with the Social Welfare department. To

enhance the mobility of specially abled persons, the Government has provided motorized tricycles.

- b. Under the merit cum means Minority Scholarship schemes, the Government ensured 210% increase in coverage from 1,43,154 (2018-19) to 3,00,651 students in 2022-23. Similarly, 169% increase in the coverage of Scheduled Caste scholarship schemes has been realized with coverage of 63,550 students in 2022-23 as against 8,250 in 2018-19.
- c. Tribal Affairs department has undertaken significant initiatives for tribal welfare in the areas of health, education, culture, literature, infrastructure development and livelihoods. Transit facilities were provided to migratory tribal communities. 8 new hostel buildings, 200 smart schools, 6 Eklavya model residential schools were developed. The Department provided dedicated coaching facilities, skill development to 2000 tribal youth and scholarships to 46,000 tribal students.

## **16. Engendering Women Empowerment**

- a. Initiatives like "Ladli Beti" and the "State Marriage Assistance Scheme" are restoring honor and respect to women in the society. Under the UT-sponsored scheme "Ladli Beti", the Government expanded coverage from 16095 cases in 2017 to 1,03,294 cases upto 2022-23. The financial assistance for the deserving girl children increased from Rs. 3 crore to Rs. 150 crore during this period.
- b. Under another UT-sponsored scheme for Marriage Assistance, 62,326 poor girls were provided financial assistance of Rs 185 crore since 2015-16 to 2021-22. This was massively stepped up during 2022-23; with 16,000 poor girls being provided Rs 80 crore marriage assistance.



- c. Efforts to empower rural women have provided dramatic results. Over seven lakh women are associated with 87,541 self-help groups. Training has been provided to around three lakh women farmers. Women farmers have established nearly two lakh agriculture nutrition gardens to meet the nutritional needs of their families. The Rural Livelihood Mission has started 10,000 micro- startups in the past one year.
- d. The Jammu and Kashmir Reorganization (Second Amendment) Bill, 2023 has been passed by Parliament, which provides for reservation of one-third of all elected seats for women in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly.

## **17. State of Economy in 2023-24**

- a. Jammu and Kashmir's economy remains on right track with the GSDP growth for current financial year (2023-24) expected to be 7.5%. The Union Territory Government continues to focus on equitable growth in all the sectors of the economy. For sustaining the developmental initiatives, the government pursued the tax and non-tax avenues judiciously.
- b. Dealer registration under GST has been expanded from about 72,000 in 2018 to 1,97,000 in 2023. Focused enforcement and dealer outreach drives have been undertaken. Capacity building of taxation staff was undertaken with support of Institute of Chartered Accountants. For stemming GST leakages, mechanism for tracking purchases was developed. For tracking GST deduction under capital works and improving tax realization, GSTN verification has been linked with bill payment system.
- c. With support of NIC, the UT initiated the e-Stamping system for registration of documents. This enhanced stamps and registration revenues from Rs. 190 crore in 2018-19 to Rs. 486 crore in 2022-23. The Union Territory Government has notified the new excise policy

and established a transparent system of auctions in allotment of liquor vends. The e-Abgari platform is being strengthened for tracking the supply chain and enhancing excise revenue. These measures have enabled revenue from GST, Excise and Stamps to register healthy growth.

- d. The revenue collection under Goods and Services Tax touched Rs 6018 crore in 2023-24 (upto December, 2023) exemplifying 10.60 percent growth over such revenues in the same period of 2022-23. The revenue from motor spirit taxes reached Rs 1240 crore in 2023-24 (till December, 2023) against the receipt of Rs 1185 crore over the same period of 2022-23. The stamp revenue has increased to Rs 416 crore upto December, 2023 against Rs 379 crore during 2022-23, showing a growth of 9.7 percent. The excise collection touched Rs 1758 crore upto ending December, 2023 against Rs 1392 crore in the same period during 2022-23, registering a growth of 26%.
- e. The overall tax collection has thus shown significant growth and resilience. Special focus was given on installing aerial bunching cables and smart meters for tracking power consumption. The installation of 4.6 lakh meters has impacted consumer behaviour and limited power consumption and also improved tariff revenue by about 10% in 2023-24. These measures enabled the Union Territory Government to accomplish several milestones across sectors.

## **18. Leveraging Direct Benefit Transfer**

- a. The Union Territory Government worked intensively to saturate all the individual beneficiary schemes and ensure 100% Aadhar seeding for beneficiaries. More than Rs 3000 crore has been disbursed to over 63 lakh beneficiaries through over 50 Direct Benefit Transfer (DBT) based welfare schemes (both cash and kind) by January 2024.
- b. Jammu and Kashmir recorded 74 crore 42 lakh e-transactions in the previous year, averaging over 2 million electronic transactions

registered daily, which is higher than many developed states. Systematic drive has been undertaken to weed out ineligible beneficiaries under ration supply and social security pensions.

- c. Aadhaar-seeding has been undertaken systematically for all welfare schemes. Through bio-metric verification and provision of e-POS machines, about Rs. 230 crore has been saved through DBT and Aadhar based verification under ration supply. Similarly, savings of over Rs 200 crore are targeted by leveraging DBT under social security schemes.

## **19. Budget 2024-25**

The budget estimates for the fiscal 2024-25 is estimated Rs 1,18,728 crore, excluding ways and means advance provision. While revenue expenditure is expected to be Rs 80,162 crore, capital expenditure is estimated to be Rs 38,566 crore.

20. Mr. Speaker, sir, I will now enumerate before this august House the sector-wise developmental goals achieved by the Union Territory Government in 2023-24.

## **21. Economic Sector**

### **21.1 Agriculture and allied sectors:**

- a) PM Fasal Bima Yojana was extended to all 20 districts this year. The Geographical Indication (GI) tag for Saffron, Mushkbudji rice, Bhaderwah Rajmash, Sulai Honey and Basmati rice has been achieved. This will ensure better product recognition and quality assurance and fetch better returns to the producers. Further, substantial work for GI tagging of unique agricultural products, like Kashmiri Lal Mirch, Kaala Zeera and Red Rice, was completed.
- b) About 2500 hectare was added under high density fruit plantation which includes 2400 hectare for sub-tropical fruits. The Water Harvesting Tanks (WHTs)/ Community Tanks, Micro irrigation system and Bore Wells are being established for assured irrigation. During the year 2023-24, 83 bore wells were constructed, which added about 100 hectare area under irrigation.

- c) Focus has been shifted to non-traditional areas for growing of specialty crops, like Mushkbudji rice, Kalazeera, Bhaderwah Rajmash etc., for increasing cropping intensity and bringing more areas under double cropping. Air transportation facility is being provided to Orchardists for transportation of perishable fruit crops like Cherry, Strawberry, Plum, Pear etc. to outside UT/Country.
- d) Under Holistic Agricultural Development Programme (HADP), nurseries are being established both under public and private sector for producing quality planting material. Six (06) walnut nurseries are being established in private sector for production of budded/grafted walnut plants. 58000 apple clonal rootstock was provided to four (04) nurseries under Private sector for multiplication and production of quality planting material.
- e) 12 cold storages with about 60000 MT capacity were commissioned. 2000 MT capacity Cold Store at Narwal, Jammu and 2500 MT capacity Cold Store at Mazbugh, Sopore were sanctioned under NABARD loan and these projects are likely to be completed in March 2024.
- f) 11,000 hectare land was added under cultivation of vegetables during 2023-24. Almost entire land, except water logged areas, in Jammu and Kashmir have been made cultivable, thereby initiating Yellow Revolution in the Union Territory. About Rs. 2852 crore has been allocated to farmers under the PM Kisan Samman Nidhi scheme so far.

**For Agriculture and allied Sectors an allocation of about Rs. 2029.95 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 500.89 crore more than revised allocation of 2023-24.**

## **21.2 Rural Development:**

- a) All the villages of Jammu and Kashmir attained ODF Plus Model Status in August 2023. During 2023-24, 25,000 individual household latrines and 563 community sanitation centres were constructed by December, 2023. During 2023-24, 10,200 more SHGs have been formed by the end of December 2023. Under MGNREGA, 182.69 lakh

mandays have been generated against the target of 200 lakh mandays in 2023-24.

- b) 396 Panchayat Ghars were taken up for construction during FY 2023-24. In 1084 Panchayat Ghars, internet connectivity has been provided through BSNL, VSAT, SWAN etc. 47,138 houses have been constructed in 2023-24 (upto December 2023) making the cumulative achievement of 1,75,273 house construction under PMAY(G) since inception of the scheme.
- c) The Rural Regional Banks (RRBs) have faced several challenges due to poor fiscal health and high establishment costs. Their performance was closely monitored for turning them around. Both the RRBs have been provided professional leadership and recapitalization support of Rs. 42 crore by the Union Territory Government during 2023-24. This will unlock further financial support of over Rs. 350 crore from the Sponsor Banks and the Central Government.

**For Rural Sector, an allocation of about Rs. 3730.83 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25.**

### **21.3 Tourism:**

- a) Jammu and Kashmir identified 75 off-beat destinations, which are being developed and promoted at international, national and local level. Funding for basic amenities has been earmarked for 10 destinations in Kashmir and 10 destinations in Jammu division. 75 heritage sites have been identified and a special scheme for Revival, Restoration, Preservation and Maintenance of Architecture and Heritage was launched.
- b) The sector witnessed unprecedented growth with over 1.88 crore tourists visiting Jammu and Kashmir in 2022. This positive trend has continued during the year 2023 with record 2.11 crore tourist arrivals. Apart from Gulmarg, Sonamarg and Pahalgam, tourists discovered the new strengths of Jammu and Kashmir. The new destinations are firmly positioning on the tourist map. Thus in 2023, tourist arrivals in Shiv Khori touched 2 million, 1.05 million in Mansar-Surinsar, 1 million in Patnitop, 1 million in Dudhpathri, and 0.15 million in Lolab.

- c) The number of foreign tourists increased 2.5 times. Off-beat destinations and border area spots are witnessed massive rise in tourist footfall. Gulmarg gondola attracted over 10 lakh tourists and generated revenue of over Rs. 100 crore during 2023-24. The work for development of new alignment and restoration and improvement of existing tracks leading to Holy Cave of Shri Amarnathji has been undertaken through the Border Roads Organization. This work has substantially improved the access, safety and convenience for the pilgrims and rejuvenate to local tourism.
- d) Eco-mobility facility was started at Sonamarg. The special train with Vista dome coach was started. The department has organized 97 events /festivals and 32 road shows to promote tourism, including promotional events at Dubai, Spain and France. In the Jammu Division, the department organized several cultural festivals, including Lohri festival, Baisakhi festival, Shivratri festival, Navratra festival, Jhiri Mela, mela Bahu Fort, Kailash yatra, Sarthal yatra, Machail yatra, Baba Chamliyal mela, Baba Sidhgoria mela, and Kounsar Nag yatra. Similarly, in Kashmir division, Border Tourism festival in Teetwal Kupwara, Gurez festival, Ketson festival in Bandipora, Badrkut festival in Tangmarg and Mundagi, and Pazalpora festival in Baramulla were widely acclaimed. Additionally, the department organized the 3-Day Sufi festival in various Kashmir districts, Downtown legacy tour, and ethnic food festivals for showcasing the cultural and culinary heritage of Jammu and Kashmir.
- e) About 102 films / web series were shot in the Union Territory in 2023. The boat club cum water sports center at Wular Lake is being upgraded to introduce water sport activities in both Wular and Mansabal lakes. Zorbing, Pedal Boating, and Jet Skiing have been introduced in Dal Lake. Water sports activities have also been organized at Mansar Lake and Ranjit Sagar Dam in the Jammu Division. Tourist Information Centres were established at strategic locations such as Baltal, Chandanwari, and Teetwal. Tourist Information Centre has been successfully built in Gurez, specifically to promote Border Tourism. Seasonal information centres have been established at both Chandanwari and Baltal to assist Shri Amarnath Ji Yatris during their pilgrimage.

**For Tourism sector, an allocation of about Rs. 357.70 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 103.95 crore more than revised allocation of 2023-24.**

#### **21.4 Forestry & Environment:**

- a) Jambu Zoo was inaugurated and started its operations in 2023-24. Over 22,000 eco-clubs have been registered as on date in the UT. So far 6722 Van Mitras and 25265 Paryavaran Mitras are enlisted. The department organized 268 events involving eco-clubs in awareness generation towards ecological conservation.
- b) The Department has rejuvenated the ponds in the forest areas by recharging the ground water through 515 water harvesting system, 7469 crates and 86710 cubic metre nallah stone check dams. The Union Territory Government ensured 99.76 lakh planting and 94.24 lakh low-cost greening interventions.
- c) 3971 village panchayats have been covered under "Har Gaon Haryali" plantation drive till December 2023. The remaining village panchayats shall be covered during winter planting season by March 2024. 4349 villages have been covered under "One Beat Guard, One Village" programme for greening of land outside forests during 2023-24 by providing free saplings and other planting material to village panchayats for planting on village common land, Kachachari and other wastelands.
- d) 135 wetlands have been cleaned and restored in the forest/ protected areas. Restoration of wetlands, like Gharana, Hokersar and Shallbugh, is being executed by way of de-silting, de-weeding and boundary delineation. PARIVESH 2.0 was launched for providing functionalities for online processing of clearance as envisaged in the Forest (Conservation) Rules, 2022.
- e) The Union Territory Government has strengthened joint forest management through emphatic recognition of forest rights of genuine persons. 5053 community forest rights and 352 individual forest rights under Forest Rights Act 2006 have been granted to Schedule Tribes and other eligible forest dweller communities.

**For Forest sector, an allocation of about Rs. 156.45 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 22 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **21.5 Cooperative Sector:**

- a) Performance of district central cooperative banks was closely tracked to improve their financial health. Anantnag Central Cooperative Bank (ACCB) and Jammu Central Cooperative Bank (JCCB) registered operating profit in the year 2023, after a span of three decades. Tata Consultancy Services (TCS) has been engaged for transitioning JCCB on the Core Banking Solution.
- b) Data of 8764 Cooperative Societies/Cooperatives has been digitized. Artisan Cards have been made available to artisans/members of Artisan Cooperatives for availing credit from Banks. Cooperative Super Bazaars of Srinagar, Jammu, Anantnag, Baramulla and Budgam have been modernized by way of face-lifting, introducing barcode scanning/ billing machines, digital display boards, etc.

**For Cooperative sector, an allocation of about Rs. 25 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 5 crore more than revised allocation of 2023-24.**

## **22. Social Sector**

### **22.1 Health and Medical Education:**

- a) Two new medical colleges at Handwara and Udhampur have been commissioned this year. This operationalization has enhanced MBBS seats by 200 in the UT. District Budgam, Anantnag & Pulwama have been certified as TB Free districts (along with revenue districts of Kulgam and Shopian). District Srinagar & Kupwara have received Gold Award for TB free districts (along with revenue district Ganderbal). District Baramulla, Udhampur, Kathua & Jammu have received Bronze award (along with revenue districts of Bandipora, Reasi & Samba). The first live Robotic Surgery demonstration was held at Government Medical College (GMC) Srinagar this year. The Cancer Institute at Jammu is being operationalized.



- b) 11476 patients were provided with de-addiction treatment in Jammu and Kashmir. During 2023-24, Non Communicable Disease (NCD) screening data for 5 NCDs viz. Hypertension, Diabetes Mellitus, Oral cancer, Cervical cancer and Breast cancer has reached 3,98,326. 80129 have been diagnosed and 80100 under treatment.
- c) E-Sehaj as part of Hospital Management Information System (HMIS) has been launched to provide various Health Services through digital platform. E-Sehaj has been integrated with the Rapid Assessment System (RAS). Health Management Information System (HMIS) and Tele-ICUs are being developed. Jammu and Kashmir achieved the top ranking among the UTs by achieving the highest number of calls in the National Tele Mental Health Programme.
- d) The Union Territory Government also conceptualized the first of its kind Chatbot for Tele- MANAS in the country to improve the accessibility to Mental Health Services. Online interventions Like e-Sanjeevani, Health Management Information System (HMIS), Scan & Share, Tele Manas etc are being widely utilized for patient management in an effective manner for optimum utilization of services of specialist and technicians.

**For Health and Medical Education Sector, an allocation of about Rs. 1427.61 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25.**

## **22.2 Education Sector:**

- a) The Union Territory Government initiated implementation of the new CSS; viz. PM- Schools for Rising India (SHRI) for developing model schools with state of art facilities. Approval has been granted for the upgradation of 233 schools in the first phase. Enrollment drive was conducted across all districts under the “Aao School Chalein” campaign and 46,000 out-of-school children were enrolled and mainstreamed. 03 Residential schools have been approved under Netaji Subhash Chandra Bose Avasiya Vidyalaya with the capacity of 100 students each.
- b) 400 smart classes and 397 additional classrooms were constructed during the current year. Free uniform were provided to all the girl

students of elementary classes and for SC/ST/PHC category boys of elementary classes. 100 percent drinking water facility has been made available in all schools. 172 ICT labs and 213 vocational labs are under construction. 02 Tribal residential schools are being set up during current year. 100 Science innovation centres containing Robotic Labs as well have been approved. 800 schools were identified for Yoga training.

- c) National Education Policy (NEP) 2020 has been fully implemented across all the schools and colleges of UT. 100% Government colleges of the UT have successfully registered on e-Samarth portal. From current academic session, the centralized admission of students through Common University Entrance Test (CUET) was started with 39954 students getting admission through this portal. NAAC accreditation of 66 Government Degree Colleges has been completed.
- d) “College on Wheels” initiative was flagged off on 19th of November, 2023 from Katra Railway Station in which 700 students along with 100 faculty members from various apex institutions travelled to different parts of the country in Jammu and Kashmir Gyanodaya Express for experiential learning and innovative exposure.

**For School and Higher Education Sector, an allocation of about Rs. 1300.10 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 201.32 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **22.3 Social Welfare & Rehabilitation:**

- a) 277 anganwadi centres have being equipped with biometric attendance system. All the anganwadi centres have been geo-tagged and the process for uploading at Gati Shakti portal is initiated. Scholarships were disbursed to 48,905 students under Pre-Matric scholarship (1st-8th) belonging to Scheduled Caste categories. The Women Help line service 181 has been established and has been integrated with the Universal helpline 112.
- b) The Union Territory administration is fully committed to the resettlement and welfare of Kashmiri Migrant families. 880 transit accommodations were constructed for Kashmiri migrants. The Union

Territory Government has provided regular government employment to over 5600 migrants under PM-Package for Kashmiri migrants. The cash assistance and food grains for Kashmiri/Jammu migrants are being continued under Security Related Expenditure.

- c) The Union Territory Government streamlined its processes for social security cover for widows, old aged and physically challenged persons.
- d) Trucks/Lorries have been provided to various districts of the UT for providing of free transhumant facilities for smooth migration of nomadic families along with livestock from upper reaches/highland pastures. Smart schools/seasonal centres, mobile medical units and livelihood support are being provided under Pradhan Mantri Van Dhan Yojana. Last fiscal year, there was a manifold increase in scholarships for the tribal community. The financial outlay was increased by over 60% to Rs. 52 crores to provide scholarships to eligible 1.90 lakh tribal students.
- e) Value Addition exercise is being conducted to explore ways to add value to tribal products. To ensure quality education for tribal community, 24 ST and Gujjar / Bakerwal hostels are being constructed. 07 transit accommodations for migratory population are being established. 07 Milk villages are being established during the current year. 158 Smart schools are being taken up for completion.

**For Social and Tribal Welfare, an allocation of about Rs. 306.82 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25. For Relief and Rehabilitation of Kashmir Migrants an allocation of Rs 1067.61 crore has been made under revenue and capital expenditure during 2024-25, which is Rs 134.68 crore more than the revised allocation of 2023-24.**

#### **22.4 Culture:**

- a) Works for restoration of important historical heritage structures, including Narastan Monument, Hari Parbat Fort, General Zorawar Singh Palace, Mubarak Mandi and SPS museum, have been started. Culture Centres are being established at Bandipora, Shopian, Anantnag, Kishtwar, Udhampur, Kathua, Jammu and Poonch. 131

libraries in the UT are being transformed into e-Libraries in a phased manner. By March 2024, 22 Libraries shall be fully transformed in e- Libraries.

- b) Abhinav Theatre at Jammu and Tagore Hall at Srinagar are being renovated and upgraded on modern lines. Structured Talent Hunt programme is under implementation in Union Territory in the four art forms; viz. painting, poetry, essay writing and singing. The Talent Hunt programmes are being organized from Panchayat to UT level. Phase-I of the New “Art Museum” at Old Secretariat, Srinagar has been completed. Phase-II is expected to be completed by March 2024.

**For Culture Sector, an allocation of about Rs. 111.50 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 51 crore more than revised allocation of 2023-24.**

## **22.5 Skill Development & Employment:**

- a) 1848 women members were upskilled under Jammu and Kashmir Rural Livelihood Mission (JKRLM) during 2023-24. The project proposals of 8 aspirational/border districts prepared by District Skill Committees have been processed for approval under Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) scheme of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Grading mechanism has been developed for grading of Industrial Training Institutes (ITIs) and Polytechnics. Skill Loans from Jammu and Kashmir Bank are being provided for aspiring candidates.
- b) 24 ITIs were registered as Nodal Skill Hubs on Skill India Portal under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 3.0. These imparted skill training to 683 candidates. 1775 candidates have been enrolled by 38 Government ITIs under the pilot phase of PMKVY 4.0. Out of these, 1383 candidates have completed the training in these institutions. Skill hubs are identified to provide skill development and vocational training opportunities to school-dropouts and out-of- school candidates.
- c) 81 job fairs have been conducted as on ending December, 2023 in which 1259 placements have been made. 41,382 units have been established under self-employment schemes, providing self

employment to 161449 unemployed youth. Six District Employment and Counseling Centers (DE&CCs) have been upgraded as Model Career Centers (MCCs). Additional 11 DE&CCs are approved as MCC by Ministry of Labour and Employment.

**For Skill Development & Employment, an allocation of about Rs. 165.50 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 82.53 crore more than revised allocation of 2023-24.**

## **22.6 Sports:**

- a) High performance centers were established in Wushu at Poonch, Billawar, Kulgam and Bakshi Stadium. Yoga centre at M A Stadium has been established & is functional. Yoga centre at Bakshi Stadium is being developed. National competitions held in Handball, Arm Wrestling, Junior National Tennis Ball, Cricket and Thang-ta. Legends League Cricket was also held at Jammu.
- b) Jammu and Kashmir hosted 04 National level events in 67th National School Games 2023, in the disciplines of Football, Volleyball, Judo & Fencing. Cricket, Football, Volleyball & Wushu academies have been established for institutionalization of Sports learning process. In addition, sports academies in disciplines of Hockey, Gymnastics, Water sports, Judo, and Table Tennis have also been set up.
- c) National coaching camps in the discipline of Wushu, Kayaking & Canoeing and Football have been organized. National events in the discipline of Handball, Deaf Cricket, Deaf Chess, Pencak silat, Rowing, Softball, Tennis Ball Cricket, Tenni-koit, Thang-ta, Wrestling Wushu, Yogasana, Water skiing and Gymnastics are being organised by the sports associations in the current financial year. Mr. Rakesh Kumar, Ms. Sarita and Ms. Sheetal Devi participated in 14th World Para Archery Championship held at Czeck Republic from 17th to 23rd July 2023 and secured 01 Gold and 01 Silver medal.
- d) At international level, Jammu and Kashmir won 6 Gold, 3 Silver, 4 Bronze medals. At national level, the UT won 56 Gold, 47 Silver and 49 Bronze medals in this year till December 2023. The UT is emerging as the winter sports capital of the nation. Over 1500 sports persons

from various States and UTs participated in the winter sports 2023 held in Jammu and Kashmir.

**For Sports sector, an allocation of about Rs. 141.80 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 31.80 crore more than revised allocation of 2023-24.**

## **22.7 Food and Civil Supplies:**

- a) By leveraging technology, the Department enhanced its logistics and efficiency in the entire supply chain of food supply. All the beneficiaries across the UT received their ration through Point of Sale (PoS) machines. The department has given focused attention for tracking of Supply Chain Management and so far 95% achievement has been registered. This digitization of stores has lowered the need of food grain inventory.

**For Food and Civil Supplies sector, an allocation of about Rs. 313 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25.**

## **23. Infrastructure Sector**

### **23.1 Power Development:**

- a) Ongoing fiscal year has witnessed improvements in electricity loss reduction and increase in revenue generation. Performance targets, as laid out in the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) Action Plan, are being vigorously pursued. Under RDSS scheme, the Department aims to install 7.6 lakh meters in Jammu division and 6.47 lakh in Kashmir division.
- b) The construction of 33 kV Bandipora-Gurez line and 11 kV trunk lines at Gurez / Tulail is under progress. For reliable power supply to Gurez, a new Grid Sub Station (GSS) of 40 MVA capacity along with the requisite 132 KV transmission line is under construction. Underground cabling through Z-Mohr Tunnel for providing 24x7 power supply to Sonamarg during winters is in process.

- c) Underground cabling at Nunwan for reliable power supply to Holy Cave of Shri Amar Nath Ji was commissioned, charged and functional. At 220/132 KV level, capacity addition of 160 MVA at existing GSS Delina has already been achieved; while as another 160 MVA is likely to be achieved by March 2024 at new Gas Insolated Grid Sub Station Tailbal, Harwan.
- d) At 132/33 KV level, a new GIS has been constructed at Tengora, Srinagar with a capacity addition of 150 MVA. Similarly, another 50 MVA capacity addition has been achieved at existing GSS Budgam. 276 MVA capacity addition is expected during CFY 2023-24 at existing GSS's at 132/33 level.

**For Power sector, an allocation of about Rs. 1875 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 552.61 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **23.2 Jal Shakti:**

- a) All the rural households will be provided tap water under Jal Jeevan Mission (JJM) to ensure 100% universal water coverage to rural households. 100% GPS system has been installed in the water tankers instead of Radio Frequency Identification (RFID) based tanker service.
- b) The digitization of consumer records is fully completed. Online billing system is now operational in Srinagar and Jammu cities. Option for consumers to pay their bills through M-Pay Service of the UT Banks has been enabled. This online billing system is being expanded to all the consumers.
- c) Flood Management programme of river Jhelum (Phase-I) is completed and has increased the carrying capacity of Jhelum from 31800 cusec to 41000 cusec at Sangam. This work on comprehensive flood management, in subsequent phases, will further increase the carrying capacity of Jhelum River. 16 works has been targeted for completion 2023-24 resulting in protection of 6500 hectare area.

**For Jal Shakti Department, an allocation of about Rs. 5038.74 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25.**

### **23.3 Housing and Urban Development:**

- a) Under AMRUT 2.0, UT Water Action Plan (UTWAP) for 153 projects for 78 ULBs of UT has been approved by Government of India. This includes 99 projects to provide 2.25 lakh new tap household water supply connections in urban areas. Under the project Devika, 03 STPs have been completed, commissioned and put on trial run. Besides, house connections and road network are being completed shortly. New projects with STP capacity of 65.33 MLD viz. sewerage scheme for Samba (3.50 MLD), pollution abatement of river Jhelum at Anantnag town zone 2 & 3 (21.03 MLD), sewerage scheme for pollution abatement of Dal-Lake, construction of STP for uncovered areas around Dal-Lake in Srinagar (30.00 MLD), STP for dry weather flow discharging into Doodh Ganga Nallah from Baghi Mehtab to Chadoora (6.0 MLD) and STP for dry weather flow discharging into Doodh Ganga (4.80 MLD) are underway.
- b) 23 projects have been undertaken for rejuvenation of water bodies with allocation of Rs. 6.11 crore. Of these, 12 projects were completed. Under Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U), 47,060 beneficiaries have been approved. Of these, 42,429 dwelling units have been grounded and 20,256 are completed. The Department is in the process of identification of feasible sites for establishment of “Ladies Haat” and Ladies exclusive markets at Srinagar, Jammu and other major towns.
- c) Under Smart Cities mission, out of 262 projects, 207 projects at an estimated cost of Rs. 4494 crore have been completed. Further, 55 projects with sanctioned cost of Rs. 2721 crore are under execution. Several innovative projects for construction of health centers, rope-way project, auditorium, power sub-stations, Girls hostel, walkways/footpaths, cycle tracks, and parking spaces have been undertaken. Smart City funding has also promoted development of green spaces, installation of LED street lights, installation of vending machines, providing smart classrooms, development of iconic roads viz. Polo view market and Apsara Road High Street Gole Market area.



- d) Comprehensive Mobility Plans for both the Capital cities were formulated. Department is promoting introduction of e-vehicles for reducing the carbon footprint and last mile connectivity for the citizen of Jammu and Srinagar cities. In this endeavor, the projects, like starting of 200 e-Buses, public bicycle sharing and providing e-Cycle and e-3 wheelers (e-Autos) are being promoted to ensure environmentally, socially, and financially sustainable network of public transport.

**For Housing and Urban Development Sector, an allocation of about Rs. 2329.55 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25.**

#### **23.4 Roads & Bridges:**

- a) The Department is constructing an average 15 km road length each day for the past four years. Overall 4500 km of black-topping of roads is expected to be achieved during 2023-24 under UT and Central Schemes.
- b) 276 new projects at an estimated cost of Rs. 1292 crore are being executed with funding under NABARD in 2022-23. Further, 183 road and bridge projects at a cost of Rs 821 crore were sanctioned and taken up in 2023-24 under NABARD funding to improve rural connectivity.
- c) Safety audit of bridges having completed 20 years has been completed during 2022-23. Safety audit for the bridges having completed 10 years has been started. 60 sanctioned bridges shall be completed during 2023-24.

**For Road and Bridge Sector, an allocation of about Rs. 4108.87 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 166 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **23.5 Industries and Commerce:**

- a) 46 new Industrial Estates (IEs) have been identified for development. Of these, 15 IE projects have been entrusted to National Buildings Construction Corporation (NBCC) and Indian Railway Construction Ltd (IRCON). 04 projects are under execution through Small Industries Development Corporation (SIDCO) and Small Scale Industries Development Corporation Ltd (SICOP). Further, 06 projects are identified for funding through SIDBI and 13 are under process of assigning to CPWD.
- b) Industrial Estate (IE) Sempora, IE Rakh Gund Aksha, Bemina and IE Lelhar Pulwama have been declared as Medicity. Online applications from the aspiring entrepreneurs/ applicants for allotment of land in the Medicities of Kashmir Division are being received. 1088 units have been sanctioned involving margin money of Rs. 29 crore having employment potential of 6528 under Jammu and Kashmir Rural Employment Generation Programme (JKREGP).
- c) Trade Promotion Organization (TPO) has organized various E-commerce on-boarding drives like GeM on-boarding, ONDC, Flipkart etc. in all the districts of Jammu and Kashmir. J&K TPO has organized 14 GeM on- boarding drives and 08 on-boarding drives with major E-commerce platforms. J&K TPO aims to onboard over 300 MSMEs on various e-commerce platforms. Samadhaan 2.0 is being implemented. The portal provides an interface to petitioners for delayed payments.
- d) During the current financial year, 24 exhibitions have been conducted. TPO has organized/ participated in 07 major events. 109 entrepreneurship development/ orientation/ awareness programmes were conducted. 105 new start-ups were registered and 7 startups were assisted in raising finance. Basohli painting, Basohli pashmina and Rajouri chikriwood have been GI tagged during 2023-24.

**For Industries and Commerce Sector, an allocation of about Rs. 529.62 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 133.35 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **23.6 Science & Technology:**

- a) Under PM Kusum scheme, 827 Solar Agriculture pumps have been installed. 955 households have been solarized in Jammu with a cumulative capacity of 5771 KW. 1102 households have been solarized under the project with a cumulative capacity of 5593 KW. The department is launching a massive drive to solarize all the Government buildings through innovative project structuring.
- b) Energy Bhawan at Channi Himmat, Jammu is likely to be completed by March 2024. Science, Technology and Innovation Council has initiated the process for establishment of Innovation dissemination center at Lal Mandi, Srinagar. The site at Chowadi, Jammu has been identified for establishment of Regional Science Centre, Jammu.

**For Science & Technology Sector, an allocation of about Rs. 159.50 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 71.50 crore more than revised allocation of 2023-24.**

### **23.7 Transport:**

- a) The Motor Vehicle Scrapping policy is being finalized. Motor Vehicle Aggregator Rules-2023 have been notified and Aggregator Licenses have been issued to OLA, Uber, AlaCab, NOVA etc. Their services have also been started in Jammu and Srinagar cities. Incentives have been kept for aggregators, aggregating motor vehicles with women drivers.
- b) Intelligent Transport Management System (ITMS) has been introduced by J&K Road Transport Corporation and online ticketing facility is available on major routes. The Department is working on commissioning the automated driving testing facility in partnership mode.

**For Transport Sector, an allocation of about Rs. 22 crore has been made under capital expenditure for the year 2024-25 which is Rs. 8.11 crore more than revised allocation of 2023-24.**

## **24 Internal Security**

- a) Construction of 42 new Border Police Posts (BPPs) in the border districts of the UT is sanctioned by the Central Government to strengthen the anti-infiltration grid in the UT. Work has been started at 21 locations and 30% of the works are completed with an expenditure of Rs. 119.83 lakh. Further, 14 Jails have been identified for construction and erection of dominant towers/jammers.
- b) Construction of hostel for families of Police Martyrs at Indra Nagar, Srinagar and Construction of Hostel for families of Police Martyrs at Assarwan, Bhalwal Jammu at an estimated cost of Rs. 20.60 crore has been approved. Narcotic Laboratory at FSL, Srinagar and Toxicology and Narcotics Laboratory at FSL, Jammu are being constructed. Physics and Ballistics Division is being established at FSL, Srinagar. CCTV surveillance system for police stations and police posts is under advanced stages of implementation.
- c) Work on Integrated network of GIS-based CCTV cameras in the identified sites of 17 districts of Jammu and Kashmir is underway for ensuring safety and security for the UT's citizens. The project's implementation will help in the identification and nabbing of anti-national elements and criminals, provide prior information on any event or incident, and enable easy and effective communication with law enforcement and other external agencies.

**For Security Related Activities, an allocation of Rs 1284.45 crore has been made for the year 2024-25 under revenue and capital expenditure.**

## **25 Supplementary Grant for the current financial year 2023-24:**

- a) The original grant for the financial year 2023-24 was Rs 1,18,500 crore. The revised estimates for 2023-24 are of the order of Rs.1,08,197 crore, excluding ways & means advance provisions. The expected revenue receipts are Rs. 84,603 crore and capital receipts are Rs.23, 594 crore. Similarly, the revenue expenditure is estimated to be Rs.76,155 crore and capital expenditure to be Rs. 32,042 crore.

- b) During the course of year from 1st April, 2023 to 31st March, 2024 an amount of Rs 8,712.8972 crore shall be withdrawn in excess of grant in respect of Demand No. 06 - Power Department, 08 – Finance Department, 24-Hospitality and Protocol and 36 – Cooperative Department out of the Consolidated Fund of the UT of Jammu and Kashmir to defray expenses on services and purposes required during the period. This had been largely necessitated due to expenses related to power purchase (Power Department), pension, interest payment, repayment of debt (Finance Department), land purchase at Dwarka, New Delhi (Hospitality and Protocol Department) and new scheme of assistance to primary agricultural credit societies (PACS) in Cooperative Department.
- c) Accordingly, the Supplementary Jammu and Kashmir Appropriation Bill No (01) is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of Rs. 8,712.8972 crore from and out of the Consolidated Fund of the UT of Jammu and Kashmir for the period w.e.f. 1st April, 2023 to 31<sup>st</sup> March, 2024.

**26. Vote on Account 2024-25 for Union Territory of Jammu and Kashmir:**

- a) The total budget estimates for the fiscal 2024-25 are Rs 1,18,728 crore, excluding the provision for ways and means advances. The expected revenue receipts are Rs. 97,861 crore and capital receipts are Rs. 20,867 crore. Similarly, the revenue expenditure is estimated to be Rs. 80,162 crore and capital expenditure to be Rs. 38,566 crore.
- b) The total receipts in respect of the proposed “Vote on Account” for 2024-25 are estimated at Rs 59,364 crore, excluding the provision for ways and means advances of Rs 16,568 crore. These receipts in respect of the proposed “Vote on Account” for 2024-25 include Rs. 48,930 crore as revenue receipts and Rs. 10,434 crore as capital receipts. The own revenues both tax and non tax are estimated to be Rs. 15,158 crore. In addition to this, Rs 18,639 crore is to flow as central assistance and Rs. 8424 crore as CSS/ PMDP to the UT of Jammu and Kashmir.
- c) The total gross receipts in respect of proposed “Vote on Account” for 2024-25 are estimated at Rs 75,932 crore, including the provision for

ways and means advances of Rs 16,568 crore. Given these receipts, the total gross expenditure is estimated to be Rs 75,932 crore. After excluding the provision for ways and means advances, the total net expenditure is estimated to be Rs 59,364 crore. This includes the estimated capital expenditure of Rs 19,283 crore and the estimated revenue expenditure Rs 40,081 crore.

- d) Accordingly, the Jammu and Kashmir Appropriation Bill No (02) in respect of "Vote on Account" is proposed to be presented to authorize payment and appropriation of Rs 75931.9699 crore from and out of the Consolidated Fund of the UT of Jammu and Kashmir.

**27. Fiscal Indicators:**

- (a) The tax/GDP ratio is projected at 7.84 percent for 2024-25 which is higher than the previous year of 6.56 %.
- (b) Debt/GDP ratio for 2024-25 is 51 %.
- (c) GDP for the year 2024-25 has been projected at Rs. 2,63,399 crore which shows a growth of 7.5 % over the previous year.

**28.** Mr. Speaker Sir, with these words, I commend the Supplementary Budget (for 01.04.2023 to 31.03.2024), and "Vote on Account" 2024-25 of the UT of Jammu & Kashmir to this august House for further consideration.